ॐ श्री सदगुरू देवाय नमः ॐ ॐ ओ३म् ॐ ॐ जय माता दी ॐ
ॐ सीताराम बाबा जी ॐ ॐ जय बाबा की ॐ ॐ श्याम बाबा ॐ ॐ
ॐ ! जाके सुमिरन तें रिपु नासा !! ! नाम सत्रुहन बेद प्रकासा !! ॐ

उल्लंघ्य सिन्धोः सलिलं सलीलं,यः शोकवहि जनकात्मजाया: आदाय तेनैव ददाह लंकां,नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्
मनोजवं मारुत तुल्य वेगं,जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं, श्रीराम दूतं शरणं प्रपद्ये

केंद्र व उत्तरांचल सरकार से विज्ञापन मान्यता प्राप्त

हिन्दी सान्ध्य दैनिक

उत्तरांचल दर्पण

♦वर्ष 26 ♦अंक 115 ♦पृष्ठ 8 ♦रुद्रपुर (ऊधमसिंहनगर) ♦शुक्रवार ♦30 जनवरी 2026 ♦मूल्य दो रूपया

darpan.rdr@gmail.com 9897427585 UTTARANCHAL DARPAN www.uttaranchaldarpan.in

भूमि विवाद मामले में डीजीपी से मिले विधायक पाण्डे

देहरादून/गदरपुर (उद संवाददाता)। जमीन कब्जाने के आरोपों और परिजनों पर हुए मुकदमे के बाद विवादों में घिरे भाजपा विधायक एवं पूर्व मंत्री अरविंद पांडे ने शुक्रवार को पुलिस मुख्यालय देहरादून पहुंचकर डीजीपी दीपम सेठ से मुलाकात की। विधायक ने इस पूरे मामले को अपने खिलाफ एक सोची-समझी साजिश करार देते हुए डीजीपी से मांग की है कि सच सामने लाने के लिए दोनों पक्षों का नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट कराया जाए। डीजीपी से मुलाकात के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए अरविंद पांडे ने बेहद कड़े शब्दों में अपनी बात रखते हुए कहा कि वह डीजीपी साहब से मुकदमा खत्म कराने की सिफारिश करने नहीं आए हैं, बल्कि वह चाहते

हैं कि इस मामले की निष्पक्ष जांच हो क्योंकि यह उन्हें 'भू-माफिया' साबित करने की एक सोची-समझी साजिश है। उन्होंने आत्म सम्मान के साथ कहा कि जब तक जांच पूरी नहीं होती, तब तक वह कागजों में 'भू-माफिया' ही हैं, इसलिए सत्यता का परीक्षण अनिवार्य है। विधायक ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि उनके परिवार का कोई भी सदस्य इस मामले में दोषी पाया जाता है, तो पुलिस उस पर कड़ी कार्रवाई करे लेकिन यदि यह साजिश है तो उसका पर्दाफाश होना चाहिए। उल्लेखनीय है कि 20 जनवरी को बाजपुर पुलिस ने फर्जी तरीके से जमीन हड़पने के आरोप में गदरपुर विधायक के भाई देवानंद पांडे सहित चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। गांव बहादुरगंज निवासी शिकायतकर्ता संजय बंसल ने तहरीर दी थी कि मुंडिया पिस्तौर स्थित उनकी जमीन पर आरोपियों ने फर्जी किरायानामा बनाकर कब्जा करने की कोशिश की है। इसी क्रम में 21 अगस्त 2025 को जिला (शेष पृष्ठ सात पर)

दूध का दूध-पानी का पानी करने के लिए 'नार्को टेस्ट' की मांग

खड़े डंपर में घुसी कार, दो की हालत नाजुक

रुड़की (उद संवाददाता)। लक्सर-हरिद्वार स्टेट हाईवे पर शुक्रवार सुबह घने कोहरे के कारण एक भीषण सड़क हादसा हो गया। श्री सीमेंट फैक्ट्री के पास सड़क किनारे खड़े एक खराब डंपर से तेज रफ्तार कार की जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार का अगला हिस्सा डंपर के नीचे घुस गया, जिससे कार चालक समेत उसमें सवार दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों की नाजुक हालत को देखते हुए उन्हें तत्काल हायर सेंटर रेफर किया गया है। जानकारी के अनुसार, उत्तर प्रदेश नंबर का एक डंपर बीती रात रुड़की के रास्ते लक्सर की ओर जा रहा था।

रात करीब एक बजे ट्रक का चेंबर खराब हो गया, जिस कारण चालक ने उसे श्री सीमेंट फैक्ट्री के पास सड़क किनारे खड़ा कर दिया। चालक ने चेंबर ठीक करने का प्रयास किया, लेकिन सफलता न मिलने पर वह ट्रक को वहीं छोड़कर चला गया। क्षेत्र में गुरुवार रात से ही घना कोहरा छाया हुआ था। शुक्रवार सुबह करीब नौ बजे जब यह हादसा हुआ, तब कोहरे के कारण विजिबिलिटी बेहद कम थी। पुलिस के मुताबिक, कार जगजीतपुर से लक्सर की ओर जा रही थी। घने कोहरे के कारण कार चालक को सड़क किनारे खड़ा डंपर दिखाई नहीं दिया और कार सीधे डंपर के पिछले हिस्से से जा टकराई। हादसे के समय हाईवे पर मॉर्निंग वॉक कर रहे लोग धमाके की आवाज (शेष पृष्ठ सात पर)

आवश्यकता है

रुद्रपुर स्थित एक प्रतिष्ठित इलेक्ट्रॉनिक शोरूम के लिए टैली अकाउंटेंट, कैशियर, स्टोर मैनेजर आदि पदों पर कर्मचारियों युवक युवतियों एवं ड्राईवर की आवश्यकता है।
-:संपर्क करें:-
8433432291

फीस वृद्धि को लेकर छात्रों का हंगामा

रूद्रपुर (उद संवाददाता)। आदर्श इन्द्रा बंगाली कालोनी स्थित कृष्णा इण्टर कॉलेज के छात्रों आज विद्यालय में अधिक फीस वसूले जाने के खिलाफ कॉलेज गेट पर जोरदार प्रदर्शन करते हुए धरना दिया। जानकारी मिलने पर कई छात्र नेता व आदर्श कॉलोनी चौकी प्रभारी भी मौके पर आ पहुंचे। बाद में छात्र नेताओं की विद्यालय प्रबन्धन से हुई वार्ता के पश्चात फीस कम किये जाने के समझौता होने पर धरना प्रदर्शन समाप्त किया गया। रोषित छात्रों का आरोप था कि विद्यालय में छात्रों से एक हजार पांच सौ रूपये प्रति माह फीस वसूली जा रही है। जो गरीब व मध्यम वर्ग के परिवारों के बच्चों के साथ अन्याय है। उन्होंने कहा कि अध्यापकों द्वारा निर्धारित फीस जमा न करने पर छात्रों का विद्यालय में प्रवेश भी रोक दिया गया। इतना ही नही छात्रों ने फीस जमा न होने पर (शेष पृष्ठ सात पर)

महाकाल दर्शन कर लौट रहे व्यवसायी मिगलानी का हृदय गति रुकने से निधन

किच्छा (उद संवाददाता)। नगर के प्रतिष्ठित व्यवसायी और विजय ट्रेडर्स के स्वामी सुनील मिगलानी के आकस्मिक निधन की खबर से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है। उज्जैन में बाबा महाकाल के दर्शन कर लौटते समय रतलाम के समीप हृदय गति रुक जाने के कारण उनका देहांत हो गया। अत्यंत मिलनसार और मृदभाषी स्वभाव के धनी सुनील मिगलानी के निधन से सामाजिक, राजनीतिक और व्यापारिक जगत में अपूर्णीय क्षति हुई है।मिली जानकारी के अनुसार, उत्तरायण पर्व के शुभ अवसर पर सुनील मिगलानी योग ग्रुप के सदस्यों के साथ महाकालेश्वर के दर्शन हेतु उज्जैन गए थे। दर्शन के पश्चात वापसी के दौरान रतलाम के पास अचानक उन्हें सीने में दर्द की शिकायत हुई और हार्ट अटैक आने से उनका निधन हो गया। उनके साथ तीर्थ यात्रा पर गए साथियों ने बताया कि देर शाम तक सभी यात्री सुनील मिगलानी की पार्थिव देह को लेकर किच्छा पहुंचेंगे। (शेष पृष्ठ सात पर)

उत्तराखंड ने बढ़ाए 'प्लास्टिक मुक्ति' की ओर कदम

-अर्श-

देहरादून। देवभूमि उत्तराखंड में अनेक प्रमुख धार्मिक स्थल होने के साथ-साथ कई विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल भी हैं, जिसके चलते उत्तराखंड में श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों की आवाजाही साल भर बनी रहती है। उत्तराखंड आने वाले श्रद्धालु एवं पर्यटक वैसे तो राज्य की आर्थिकी में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान देते हैं लेकिन वे अपने इस योगदान साथ-साथ उत्तराखंड एवं पर्यावरण की दृष्टि से अति संवेदनशील उच्च हिमालय क्षेत्र को वेस्ट प्लास्टिक के रूप में एक बड़ी सिरदर्दी भी दे जाते हैं। समूचे उत्तराखंड के साथ-साथ उच्च हिमालय क्षेत्र में जहां-तहां फेंक दिए जाने वाले वेस्ट प्लास्टिक के संभावी दुष्परिणाम के प्रति पर्यावरण विद् सरकार को अनेक बार चेता चुके हैं पर्यावरण विज्ञानियों की चेतावनी और मशवरे को गंभीरता से लेते हुए उत्तराखंड सरकार ने अब सूबे को प्लास्टिक मुक्त

राजधानी में लगाई गई प्लास्टिक वेस्ट क्रशर मशीन,सिंगल यूज प्लास्टिक बोतल को क्रश करके बनाए जाएंगे फर्नीचर एवं सड़क

बनाने की ओर कदम बढ़ा दिए हैं और प्लास्टिक मुक्त उत्तराखंड' के संकल्प को मूर्त रूप देने की गरज से राज्य की राजधानी देहरादून के दून अस्पताल चौक में एक ऑटोमेटिक प्लास्टिक बोतल क्रशर मशीन की शुरुआत की है।इस मशीन से सिंगल यूज बोतल को क्रश किया जाएगा। नगर आयुक्त नमामि बंसल ने बताया कि ऑटोमेटिक प्लास्टिक बोतल क्रशर मशीन का मुख्य उद्देश्य प्लास्टिक के बढ़ते प्रदूषण पर नियंत्रण करना है। साथ ही प्लास्टिक वेस्ट से टेबल, चेयर, फ्लावर पॉट और घर की सजावटी वस्तुओं को बनाने पर फोकस रहेगा। इस ऑटोमेटिक मशीन का संचालन मनसा फैसिलिटी एंड प्राइवेट लिमिटेड की ओर से किया जा रहा है, जो कि प्लास्टिक की बोतलों को रिसाइकिल करेगा। एक करार के तहत नगर निगम रिसाइकल रॉ मैटेरियल को सीधा खरीदेगा तथा रीसायकल रा मटेरियल द्वारा फर्नीचर आदि तैयार कर शहर के मुख्य चौराहे पर इस्तेमाल करेगा। नगर निगम देहरादून की इस अभिनव पहल से न केवल शहर की स्वच्छता व्यवस्था मजबूत होगी, बल्कि (शेष पृष्ठ सात पर)

प्रदेश में एक अप्रैल से होगा कचरे का चार स्तरीय पृथक्करण , सख्ती से लगेगा पर्यावरणीय जुर्माना

देहरादून। एक अप्रैल से लागू होने जा रही ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2026 के तहत अब कचरे को केवल गीले और सूखे में नहीं, बल्कि चार अलग-अलग श्रेणियों गीला, सूखा, स्वच्छता अपशिष्ट और विशेष देखभाल अपशिष्ट में पृथक करना अनिवार्य होगा। केंद्र सरकार का उद्देश्य कचरे के बेहतर प्रसंस्करण और पर्यावरण संरक्षण को मजबूत करना है, लेकिन उत्तराखंड में इस व्यवस्था को धरातल पर उतारना इतना आसान नहीं होगा।राज्य की मौजूदा स्थिति यह है कि स्रोत स्तर पर गीला-सूखा कचरा पृथक्करण ही अभी पूरी तरह सफल नहीं हो पाया है। पहाड़ी क्षेत्रों में तो हालात और भी चुनौतीपूर्ण हैं, जहां आज भी कई घरों में सारा कचरा एक ही डिब्बे में डाल दिया जाता है। ऐसे में चार डिब्बों की व्यवस्था लागू करना शहरी निकायों के लिए बड़ी परीक्षा साबित हो सकता है। स्वच्छता सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश के प्रमुख शहरों में घर-घर स्तर पर गीला-सूखा कचरा अलग करने की स्थिति अभी संतोषजनक नहीं है। देहरादून में अधिकतम 60 प्रतिशत, हरिद्वार में 55, ऋषिकेश में 50 से 55 प्रतिशत के बीच बताया जा रहा है। हल्द्वानी में यह आंकड़ा करीब 50 प्रतिशत, रुद्रपुर में 45 से 50 प्रतिशत और काशीपुर में 40 से 45 प्रतिशत के आसपास है। वहीं अल्मोड़ा, पौड़ी, टिहरी और पिथौरागढ़ जैसे पहाड़ी नगरों में औसतन केवल 30 से 40 प्रतिशत घरों में ही गीला-सूखा कचरा अलग किया जा रहा है। शहरी विकास विभाग भी मानता है कि ये आंकड़े भी काफी हद तक औपचारिक हैं, वास्तव में कई क्षेत्रों में स्रोत स्तर पर पृथक्करण की स्थिति इससे भी कमजोर है। **अब चार-स्तरीय पृथक्करण : गीला कचरा- रसोई अपशिष्ट, सब्जी-फल के छिलके, फूल, मांस आदि। सूखा कचरा- प्लास्टिक, कागज, कांच, धातु। स्वच्छता अपशिष्ट- डायपर, सैनिटरी पैड, टैम्पोन, कंडोम। हानिकारक कचरा- पेंट डिब्बे, बल्ब, थर्मामीटर, दवाइयां।** चार-स्तरीय व्यवस्था को लागू करने के लिए केवल नियम बनाना ही पर्याप्त नहीं है। इसके लिए घरों, दुकानों, होटलों व संस्थानों में चार अलग-अलग डस्टबिन, कचरा उठाने वाली गाड़ियों में अलग-अलग खांचे, और अंत में इनके लिए अलग प्रसंस्करण एवं निपटान केंद्र जरूरी होंगे। उत्तराखंड के अधिकांश नगर निकायों के पास न तो अभी इसके लिए पर्याप्त संसाधन हैं और न ही स्वच्छता कर्मियों की संख्या, जिससे यह व्यवस्था तुरंत लागू की जा सके। नए नियमों में प्रदूषक भुगतान सिद्धांत को भी सख्ती से लागू कराने की पैरोकारी की गई है। नियमों का पालन न करने पर व्यक्ति, संस्था या थोक अपशिष्ट उत्पादक पर पर्यावरणीय जुर्माना लगेगा। इससे शहरी निकायों को कार्रवाई का कानूनी आधार तो मिलेगा, लेकिन बिना पर्याप्त तैयारी के यह प्रविधान आम नागरिकों और छोटे व्यापारियों के लिए परेशानी का कारण भी बन सकता है।

स्कूल में घुसकर युवक ने प्रधानाध्यापिका समेत कई शिक्षकों को पीटा, मुकदमा दर्ज

डोईवाला। राजकीय प्राथमिक विद्यालय तेलीवाला में प्रार्थना सभा के दौरान विद्यालय के समीप रहने वाले एक युवक ने विद्यालय की प्रधानाध्यापिका समेत तीन शिक्षकों के साथ मारपीट कर दी, साथ ही विद्यालय की बालिकाओं के विरुद्ध अश्लील टिप्पणी भी की।घटना के बाद क्षेत्र का माहौल एकदम बदल गया और शिक्षकों के साथ ही हिंदू संगठन से जुड़े तमाम लोग कोतवाली में पहुंचे जहां पर उन्होंने आरोपित के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की। वहीं पुलिस ने मामले की जानकारी मिलते ही तत्काल आरोपित को गिरफ्तार कर लिया, साथ ही संगीन धाराओं में उसके विरुद्ध मुकदमा भी दर्ज किया है। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक प्रदीप कुमार राणा ने बताया कि राजकीय प्राथमिक विद्यालय तेलीवाला की प्रधानाध्यापिका उषा रानी ने कोतवाली में शिकायत देते हुए बताया कि प्रार्थना सभा के दौरान विद्यालय के सामने रहने वाले एक युवक ने विद्यालय

में पहुंचकर बालिकाओं के साथ अश्लील टिप्पणी की और अभद्र भाषा का प्रयोग किया, रोकने पर उनके अलावा दो अन्य शिक्षकों के साथ मारपीट की। साथ ही विद्यालय में आग लगाने व जान से मारने की धमकी भी दी गई ओर विद्यालय का फर्नीचर आदि भी तोड़ा गया। उन्होंने बताया कि आरोपित पूर्व में भी विद्यालय में इस तरह की हरकतें कर चुका है। जिससे छात्र-छात्राओं के साथ ही अध्यापकों में भी आरोपित से भय बना हुआ है। प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि शिकायत के आधार पर आरोपित मोहम्मद सरफराज उर्फ मोनू पुत्र हनीफ निवासी तेलीवाला डोईवाला के विरुद्ध स्वेच्छा से चोट पहुंचाने, लोक सेवक को उसके कर्तव्य के दौरान चोट पहुंचाने, संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, हमला करना, अपराधिक धमकी, अपमान करने, महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने आदि भारतीय न्याय संहिता की सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। मामले में अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।

शहरी क्षेत्र में एसआईआर का सत्यापन धीमा, तहसीलदार ने बीएलओ के साथ की मीटिंग

सितारगंज।ग्रामीण क्षेत्र के मुकाबले शहरी क्षेत्र में एसआईआर का सत्यापन काफी धीमा हैं। बीएलओ के समक्ष दस्तावेजों के सत्यापन को लेकर तमाम तरह की दिक्कतें सामने आ रही हैं। तकनीकी संसाधनों का मतदाता लाभ नहीं ले पा रहे हैं। इसके अलावा शहरी क्षेत्र में दूसरे राज्य के लोगों की बढ़ी हुई जनसंख्या भी सत्यापन अभियान की गति को धीमा कर रही हैं। शुक्रवार को तहसीलदार हिमांशु जोशी ने शहरी क्षेत्र के समस्त बीएलओ के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने बीएलओ से एसआईआर सत्यापन के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी। बीएलओ ने बताया कि कुछ स्थानों पर सत्यापन अभियान को लेकर दिक्कत है सामने आ रहे हैं। समीक्षा मीटिंग में मौजूद जिम्मेदारों ने बताया कि शहरी क्षेत्र में एसआईआर के सत्यापन को पहुंचने के बाद कुछ स्थानों में जागरूकता की काफी कमी हैं। कुछ स्थानों पर मोबाइल लेकर महिलाओं के पति काम पर चले जाते हैं। जिस वजह से तकनीकी कार्य सम्पन्न नहीं हो पा रहे हैं। बताया जाता है कि शहरी क्षेत्र में एसआईआर सत्यापन 50 प्रतिशत ही पूर्ण हो चुका हैं। जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में एसआईआर 85 प्रतिशत सत्यापन अभियान पूर्ण हो चुका है। इसके अलावा शहरी क्षेत्र में बाहरी राज्यों के लोगों की अधिक संख्या होने से भी एसआईआर में समस्याएं सामने आ रही हैं। तहसीलदार हिमांशु जोशी ने सत्यापन अभियान को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं।

यातायात नियमों और साइबर अपराध पर दी जानकारी

भीमताल। उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के दिशा-निर्देशानुसार और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के अध्यक्ष व जिला न्यायाधीश प्रशांत जोशी के निर्देशन में नगर पालिका परिषद भीमताल में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव व सिविल जज (सी.डी.) पारुल थपलियाल की अध्यक्षता में आयोजित इस शिविर में स्थानीय नागरिकों को कानून की बारीकियों और सुरक्षा मानकों से अवगत कराया गया। शिविर में थानाध्यक्ष शिवराज सिंह बिष्ट ने यातायात सुरक्षा और मोटर वाहन अधिनियम के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह कानून सड़क परिवहन, वाहनों के पंजीकरण और ड्राइविंग लाइसेंस को नियंत्रित करने वाला मुख्य आधार है। उन्होंने सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए ट्रैफिक नियमों का पालन करने और लापरवाह चालकों के लिए निर्धारित दंड के प्रावधानों के बारे में बताया। इसके साथ ही दुर्घटना की स्थिति में पीड़ित को मुआवजा दिलाने के लिए अनिवार्य बीमा

और प्रदूषण नियंत्रण के मानकों पर भी चर्चा की गई। वहीं सब इंस्पेक्टर गुरविंदर कौर ने साइबर अपराध के बढ़ते खतरों के प्रति आगाह किया और ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचने के मुख्य बिंदुओं की जानकारी दी। सचिव पारुल थपलियाल ने शिविर में उपस्थित जनसमूह को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के क्रियाकलापों के बारे में बताया। उन्होंने महिला प्रतिकार योजना और टोल फ्री नंबर 15100 के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि यदि किसी भी व्यक्ति को कानूनी सहायता की आवश्यकता हो, तो वह प्राधिकरण से संपर्क कर निःशुल्क सहायता प्राप्त कर सकता है।

गांवों में गठित होंगी सुरक्षा समितियां

शक्तिफार्म (उद संवाददाता)। क्षेत्र में कानून-व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने और अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने के उद्देश्य से शक्तिफार्म पुलिस चौकी में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। कोतवाल सुंदरम शर्मा की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में क्षेत्र के ग्राम प्रधानों, नगर पंचायत अध्यक्ष और सभासदों ने हिस्सा लिया। बैठक का मुख्य एजेंडा पुलिस और जनता के बीच समन्वय स्थापित कर सुरक्षित वातावरण तैयार करना रहा।बैठक के दौरान कोतवाल सुंदरम शर्मा ने प्रत्येक गांव में 'सुरक्षा समिति' गठित करने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि ग्राम स्तर पर सक्रिय समितियों के माध्यम से असामाजिक तत्वों पर नजर रखना आसान होगा और पुलिस को समय रहते सटीक सूचनाएं मिल सकेंगी। कोतवाल ने क्षेत्र में नशाखोरी,

चोरी और अन्य सामाजिक बुराइयों पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि इन समस्याओं के जड़ से खात्मे के लिए जनसहयोग अनिवार्य है। उन्होंने जनप्रतिनिधियों से अपील की कि वे अपने क्षेत्रों में लोगों को जागरूक करें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस को साझा करें।जनप्रतिनिधियों ने पुलिस प्रशासन की इस पहल का स्वागत करते हुए हरसंभव सहयोग देने का भरोसा दिलाया। वक्ताओं ने कहा कि सुरक्षा समितियों के बनने से गांवों में निगरानी तंत्र मजबूत होगा और असामाजिक तत्वों में डर पैदा होगा। इस बैठक को क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और सामाजिक सौहार्द बनाए रखने की दिशा में एक बड़ी और सकारात्मक पहल माना जा रहा है।

विश्व के कण-कण में है शिव तत्व की थिरकन - डॉ. सर्वेश्वर

हल्द्वानी (उद संवाददाता)। दिव्य ज्योति जाग्रति संस्थान द्वारा एम. बी. इंटर कॉलेज ग्राउंड में 29 जनवरी से 4 फरवरी 2026 तक सात-दिवसीय भगवान शिव कथा के प्रथम दिवस दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी के शिष्य कथा व्यास डॉ. सर्वेश्वर जी ने कथा माहात्म्य का वर्णन करते हुए बताया कि भगवान शिव की महिमा तो ऐसी है जो देश-काल की समस्त सीमओं से परे विश्व के कण-कण में समाहित है। आज केवल भारत ही नहीं अपितु सम्पूर्ण विश्व में भगवान शिव के असंख्य भक्त उनकी उपासना करते हैं। यदि विश्व की विभिन्न प्राचीन सभ्यताओं की ओर दृष्टिपात करें तो वहाँ भी भगवान शिव की उपासना के असंख्य प्रमाण मौजूद हैं। उदाहरण स्वरूप तुर्किस्तान के बेबीलोन शहर में एक हजार दो सौ फुट का एक विशाल शिवलिंग पाया गया है।स्कॉटलैंड में स्वर्णजड़ित एक विशाल शिवलिंग है। आयरलैंड के तारा हिल में एक बहुत पुराना शिवलिंग स्थापित है। दक्षिण अफ्रीका के ब्राजील शहर में अनेकों शिवलिंग हैं। इसी प्रकार मेक्सिको, जावा, कम्बोडिया, सुमात्रा, नेपाल, भूटान, इटली, यूरोप आदि देशों में विभिन्न प्राचीन शिवलिंग होने के प्रमाण मिले हैं। ये सब साक्ष्य भगवान शिव की सर्वगम्यता व असीमित लोकप्रियता को ही दर्शाते हैं। विदेशी आक्रमणों के बाद भी यदि भारतीय संस्कृति प्रफुल्लित साँसें भर रही है तो इसका एकमात्र कारण है इसकी धमनियों में प्रवाहित होता शिव तत्व। या यूँ कहें, भारत देश की तो आत्मा ही महादेव हैं। लेकिन अफसोस, आधुनिकता की अंधी दौड़ में दौड़ती भारत देश की संतानें आज शिव तत्व से कोसों दूर हो पतन की गहरी खाई में लुढ़कती चली जा रहीं हैं। आज समाज में व्याप्त हिंसा, वैमनस्य, मतभेद सब शिव तत्व का समाज से विलुप्तिकरण ही दर्शाते हैं। प्रभु की यह पावन कथा उसी सनातन शिव तत्व को उजागर करने आई है। शिव तत्व को ब्रह्मज्ञान के माध्यम से घट में प्रकट करने आई है। ताकि शिव की संतानें "सत्यंम शिवम सुन्दर" के सूत्र का अनुसरण करते हुए इस मायायुक्त संसार में सत्य का वरण कर शिवपथ अर्थात् कल्याणकारी पथ पर आगे बढ़ें और अपने जीवन को सुंदर बना लें। कथा का समापन प्रभु की पावन आरती से किया गया। इस दौरान डॉ. जे. आर. धपोला, निर्मला धपोला, डॉ. पवन दीप धपोला, रितेश डाबर, एकता डाबर, अंकित शर्मा, गीता बुलुटिया, राजेश अग्रवाल, प्रताप बिष्ट, मुकेश बोरा, बालकिशन अग्रवाल आदि मौजूद रहे।

यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन के खिलाफ प्रदर्शन कर जलाई प्रति

हल्द्वानी (उद संवाददाता)। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा लागू किए गए एक्ट के विरोध में बुधवार को व्यापक जनाक्रोश देखने को मिला। विभिन्न सामाजिक संगठनों, स्वर्ण समाज, व्यापारिक संगठनों और युवाओं के संयुक्त आवाहन पर बुद्ध पार्क में एक वृहद बैठक आयोजित की गई, जिसमें बड़ी संख्या में छात्र, शिक्षक, व्यापारी, सामाजिक कार्यकर्ता और आम नागरिक शामिल हुए। बैठक के पश्चात प्रदर्शनकारियों ने बुद्ध पार्क से एसडीएम कोर्ट तक पैदल मार्च निकालते हुए यूजीसी के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने यूजीसी के नए इक्विटी रेगुलेशन को "काला कानून" बताते हुए कहा कि यह नियम उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता के नाम पर भय, अविश्वास और जातिगत विभाजन को बढ़ावा दे रहा है। वक्ताओं ने आरोप लगाया कि इस कानून में झूठी शिकायतों पर कोई सख्त दंडात्मक प्रावधान नहीं है, जिससे शिक्षकों और छात्रों को मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ सकती है और उनका भविष्य खतरे में पड़ सकता है। आक्रोश के प्रतीक स्वरूप प्रदर्शनकारियों ने यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन की प्रति जलाकर विरोध दर्ज कराया। रैली के बाद प्रदर्शनकारी एसडीएम कोर्ट पहुंचे, जहां उपजिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को ज्ञापन प्रेषित किया गया। ज्ञापन में यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन 2026 को तत्काल निरस्त करने की मांग करते हुए कहा गया कि यह कानून संविधान के समानता के अधिकार और सामाजिक समरसता की भावना के विपरीत है। ज्ञापन में सरकार को एक सप्ताह का समय देते हुए चेतावनी दी गई कि यदि इस अवधि में कानून वापस नहीं लिया गया, तो हल्द्वानी में वृहद महापंचायत आयोजित कर आंदोलन को उग्र रूप दिया जाएगा। उत्तराखंड युवा एकता मंच के संयोजक पीयूष जोशी ने कहा कि सरकार को एक सप्ताह का स्पष्ट अल्टीमेटम दिया गया है। यदि इस अवधि में यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन वापस नहीं लिया गया तो एक बड़ी महापंचायत के साथ-साथ उग्र आंदोलन किया जाएगा।विधायक सुमित हृदेश ने कहा कि यह कानून समाज को जोड़ने के बजाय तोड़ने का कार्य कर रहा है। सरकार को बिना सभी वर्गों को विश्वास में लिए ऐसे संवेदनशील कानून लागू नहीं करने चाहिए। यदि यह कानून वापस नहीं हुआ तो वह इस मुद्दे को सड़क से लेकर सदन तक मजबूती से उठाएंगे।व्यापार मंडल अध्यक्ष संदीप पांडे ने कहा कि शिक्षा समाज की रीढ़ है और यदि शिक्षा संस्थानों में डर और भेदभाव का माहौल बनाया गया तो इसका सीधा असर व्यापार, रोजगार और सामाजिक संतुलन पर पड़ेगा। शिक्षक सुभाष कांडपाल ने कहा कि ब्राह्मण एवं स्वर्ण समाज के साथ लगातार जातिगत आधार पर भेदभाव किया जा रहा है, जो गंभीर चिंता का विषय है। सुराज सेवा दल के कुमाऊं मंडल अध्यक्ष विशाल शर्मा ने कहा कि यूजीसी द्वारा लागू किया गया इक्विटी रेगुलेशन 2026 शिक्षा के क्षेत्र में समानता लाने के बजाय समाज को जातिगत आधार पर बांटने का काम कर रहा है। पहाड़ी आर्मी संगठन के अध्यक्ष हरीश रावत ने कहा कि यह कानून सामाजिक एकता को कमजोर करेगा। वहीं स्वराज हिंद मंच के संस्थापक सुशील भट्ट ने कहा कि यह नियम समाज में अविश्वास और विभाजन पैदा करने वाला है।कार्यक्रम के संयोजक प्रकाश हर्बोला ने कहा कि हम लोग संगठित होकर अभी भी इसका विरोध नहीं करेंगे तो हम अपने आने वाली पीढ़ी को क्या देंगे गुलामी या फिर अनपढ़ गवारु मजदूर बनाएंगे अभी समय है सभी संवर्ण समाज एक होकर इस कानून का विरोध करें। जेएस बिष्ट पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डिप्लोमा इंजीनियर्स ने कहा हमें आज संगठित होने की अत्यंत आवश्यकता है। भुवन भट्ट ने कहा कि यूजीसी कानून मे सभी विद्यार्थियों को समान रूप से शिकायत करने का अधिकार होना चाहिए शिकायत करने वाला शपथ पत्र दे अगर शिकायत झूठी निकले तो उसके लिए दोगुना दंड का प्रावधान हो।राजपूत परिषद की शांति जीना ने कहा हमें ठाकुर पंडित, बनिया कायस्थ भूमिहार के रूप में नहीं सोचना है हम यही सोच रहे है इसलिए कानून द्वारा हमें दबाया जा रहा है हम सबने मिलकर इसका प्रतिकार करना चाहिए। इस दौरान पलक अग्रवाल, अध्यक्ष महिला अग्रवाल सभा , ट्रांसपोर्ट यूनियन अध्यक्ष प्रदीप सबरवाल,संरक्षक ट्रांसपोर्ट यूनियन इंदर भुटियानी,हर्षवधन पांडे, भुवन भट्ट, देवीदयाल उपाध्याय ,राजेंद्र सिंह, राहुल झीगरन,त्रिलोक बिष्ट,मनोज अग्रवाल,नीतू अग्रवाल, नितिन बोरा हिमांशु मेहता, निखिल बिष्ट, देव सिंह, मोहित बिष्ट, पारस जोशी, सूरज बिष्ट, रोहित बिष्ट, भैरव देवता, मोहित जोशी, उदय जोशी, विनोद पाठक, मोहन पाठक, विशाल शर्मा सहित बड़ी संख्या में सामाजिक कार्यकर्ता और युवा मौजूद रहे।

उत्तराखंड में पहली बार शुरू हुआ पीएलएफएस सर्वेक्षण,रोजगार आंकड़ों का होगा सटीक आकलन

देहरादून (उद संवाददाता)। उत्तराखंड में रोजगार और बेरोजगारी की वास्तविक स्थिति का सटीक पता लगाने के लिए अर्थ एवं संख्या निदेशालय (नियोजन विभाग) ने पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे (पीएलएफएस) की शुरुआत कर दी है। इस महत्वपूर्ण सर्वेक्षण के लिए शोध विकास एवं प्रशिक्षण संस्थान (आईआरडीटी), सर्वे चौक में दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। राज्य सरकार द्वारा पहली बार प्रदेश के सभी जनपदों में इस सर्वेक्षण को अपने स्तर से संचालित किया जा रहा है, जो भारत सरकार के सांख्यिकी कार्यक्रम एवं क्रियान्वयन मंत्रालय की सामाजिक-आर्थिक इकाई के माध्यम से संचालित होता है।यह सर्वेक्षण उत्तराखंड के ग्रामीण और नगरीय दोनों क्षेत्रों में समान रूप से चलाया जाएगा। अर्थ एवं संख्या विभाग के जनपद और विकासखंड स्तरीय कार्मिक इसे एक निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करेंगे। इस सर्वे का मुख्य उद्देश्य राज्य में श्रम बल भागीदारी और बेरोजगारी दर का वैज्ञानिक ढंग से आकलन करना है। इसके माध्यम से न केवल रोजगार की वास्तविक स्थिति का विश्लेषण हो सकेगा, बल्कि संगठित और असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों की आय का भी निर्धारण किया जाएगा, जिससे भविष्य की नीतियों में सुधार संभव होगा।प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए अर्थ एवं संख्या निदेशक सुशील कुमार ने आंकड़ों की शुद्धता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि डेटा संकलन में पारदर्शिता और सावधानी बरती जाए ताकि राज्य की विकास योजनाओं के लिए एक विश्वसनीय आधार तैयार हो सके। इस अवसर पर अपर निदेशक पंकज नैथानी ने भी अपने विचार साझा किए। कार्यशाला में संयुक्त निदेशक डॉ. दिनेश बडोनी, चित्रा, डॉ. ईला पन्त बिष्ट, उप निदेशक निर्मल कुमार शाह, लालित मोहन जोशी, अर्थ एवं संख्याधिकारी अशोक कुमार और अपर सांख्यिकी अधिकारी नरेन्द्र सिंह सहित सभी जनपदों के अधिकारी और सहायक संख्याधिकारी मौजूद रहे।

पांच छात्र-छात्राओं का सरकारी सेवा में चयन

ग्रीन वर्ल्ड पब्लिक स्कूल के पूर्व विद्यार्थियों ने रचा इतिहास

शक्तिफार्म (उद संवाददाता)। ग्रीन वर्ल्ड पब्लिक स्कूल शक्तिफार्म के लिए यह गर्व और गौरव का क्षण है। विद्यालय के पांच पूर्व छात्र-छात्राओं ने विभिन्न सरकारी पदों पर चयनित होकर क्षेत्र का नाम रोशन किया है। इन होनहारों की उपलब्धि की सूचना मिलते ही विद्यालय और पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ गई है। सफलता की इस सूची में विद्यालय की पूर्व छात्रा एवं शिक्षिका सुनीता दास और सुष्मिता सरकार का नाम शामिल है, जिनका चयन प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के पद पर हुआ है। वहीं, विद्यालय के पूर्व छात्र रंजीत राठौर, देवेन्द्र सिंह बिष्ट और महिपाल सिंह फर्त्याल ने भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) में चयनित होकर देश सेवा की राह चुनी है। इस बड़ी सफलता पर विद्यालय प्रबंधन द्वारा प्रार्थना स्थल पर एक विशेष सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में चयनित छात्र-छात्राओं को स्मृति चिन्ह भेंट किए गए और उनके अभिभावकों को शाल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया।चयनित विद्यार्थियों ने अपनी इस सफलता का श्रेय अपने माता-पिता और गुरुजनों के मार्गदर्शन को दिया। उन्होंने विशेष रूप से नवीन जोशी को अपने जीवन का मार्गदर्शक बताया। साथ ही प्रधानाचार्य सदानन्द विश्वास, व्यायाम शिक्षक प्रकाश सिंह बोरा, भगवती प्रसाद उप्रेती, प्रेमा बिष्ट और नर्सरी कक्षा की अध्यापिका विमला ढौंडियाल का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर नारायण सरकार, प्रतिभा रानी दास, दिनेश दास, सेवा राम राठौर, कुसुम देवी, ऋचा राठौर, कमला देवी, धरम सिंह बिष्ट, हीरा देवी, भगवान चन्द्र पन्त, अजय शाह सहित समस्त विद्यालय स्टाफ ने उपस्थित रहकर चयनित विद्यार्थियों को उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं।

समूहों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए वालेट पार्किंग और कॉल सेंटर बनाने के निर्देश

भीमताल (उद संवाददाता)। मुख्य विकास अधिकारी अरविंद पाण्डे की अध्यक्षता में विकास भवन में ग्रामोत्थान रीप परियोजना की समीक्षा बैठक संपन्न हुई। बैठक में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने और महिला स्वयं सहायता समूहों को स्वावलंबी बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मुख्य विकास अधिकारी ने एरोमेटिक पौधों के रोपण के प्रति महिलाओं को जागरूक करने के लिए सितारगंज में एक्सपोजर विजिट कराने के निर्देश दिए। साथ ही रीप परियोजना के तहत 'अल्ट्रा पुअर' वर्ग के उत्थान के कार्यों में तेजी लाने पर जोर दिया। उन्होंने समस्त खंड विकास अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे रीप और एनआरएलएम योजनाओं का समय-समय पर निरीक्षण करें और नियमित बैठकों के साथ आख्या प्रस्तुत करें।मुख्य विकास अधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि आगामी 15 फरवरी तक सभी रीप और एनआरएलएम कार्मिक अपना-अपना नवाचारी प्लान प्रस्तुत करेंगे। क्षेत्र में पार्किंग की समस्या के समाधान के लिए उन्होंने वालेट पार्किंग के निर्माण हेतु स्थल चयन के निर्देश दिए, जिसका संचालन समूहों को सौंपा जाएगा ताकि उन्हें स्वरोजगार के अवसर मिल सकें। इसके अतिरिक्त उन्होंने महिलाओं को योगा ट्रेनर के रूप में तैयार करने, फुटबॉल खेल टर्फ और क्रिकेट बॉलिंग प्रैक्टिस मशीन का संचालन समूहों से कराने के भी सुझाव दिए ताकि समूहों की आय में वृद्धि हो सके। नेटल ग्रास फैब्रिक के उत्पादन के लिए भी एक्सपोजर विजिट कराने और समूहों के माध्यम से काम शुरू करने की बात कही गई।बैठक में झीलों और अमृत सरोवरों के सौंदर्यीकरण का कार्य भी समूहों के माध्यम से कराने पर चर्चा हुई। महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए ब्यूटी पार्लर का प्रशिक्षण देने के निर्देश दिए गए। मुख्य विकास अधिकारी ने खंड विकास अधिकारी भीमताल और धारी को मॉडल विलेज सुनकिया के कार्यों में प्रगति लाने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने समूहों का एक कॉल सेंटर बनाने की योजना पर काम करने को कहा, जहाँ से टीवी, फ्रिज जैसे उपकरणों की मरम्मत के लिए त्वरित सेवा प्रदान की जा सकेगी। बैठक में जिला विकास अधिकारी गोपाल गिरी, सहायक परियोजना निदेशक चन्दा फर्त्याल सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

यूजीसी मामले में सुप्रीम कोर्ट का आदेश लोकतंत्र की जीत: गणेश

किच्छा (उद संवाददाता)। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) से जुड़े मामले में सर्वोच्च न्यायालय के ताजा आदेश का कांग्रेस ने स्वागत किया है। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रवक्ता और पूर्व मुख्यमंत्री सलाहकार डॉ. गणेश उपाध्याय ने इसे लोकतंत्र और संविधान की विजय करार दिया। उन्होंने कहा कि यह फैसला संवैधानिक संस्थाओं की स्वायत्तता और देश की शिक्षा प्रणाली की रक्षा की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा।डॉ. उपाध्याय ने कहा कि न्यायालय का हस्तक्षेप इस बात का स्पष्ट संकेत है कि किसी भी सरकार को संविधान की सीमाओं के भीतर रहकर ही निर्णय लेने होंगे। उन्होंने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बयानों का हवाला देते हुए कहा कि राहुल गांधी लगातार चेतावनी देते आए हैं कि पिछले 11 वर्षों में लोकतांत्रिक मूल्यों और संवैधानिक मर्यादाओं को कमजोर करने की कोशिश की गई है। यूजीसी को लेकर आया अदालत का यह आदेश इस बात की पुष्टि करता है कि संविधान से ऊपर कोई सत्ता नहीं है और संस्थागत संतुलन बनाए रखना अनिवार्य है।कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि शिक्षा और युवाओं के भविष्य को लेकर राहुल गांधी द्वारा व्यक्त की गई चिंताएं आज और अधिक प्रासंगिक हो गई हैं। यह निर्णय सरकार को संविधान के प्रति जवाबदेह बनाता है और यह स्पष्ट करता है कि जनहित के मुद्दों पर एकतरफा फैसले स्वीकार्य नहीं होंगे। उन्होंने संतुलित दृष्टिकोण रखते हुए कहा कि यह निर्णय किसी राजनीतिक दल के विरुद्ध नहीं, बल्कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए है।

मुख्यमंत्री ने की रोजगार एवं स्वरोजगार से जुड़ी योजनाओं की समीक्षा

स्वरोजगार के लिए अधिकतम अवसर उपलब्ध कराने हेतु विभागों को तेजी से कार्य करने के निर्देश

देहरादून (उद संवाददाता)। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को सचिवालय में कृषि, पशुपालन, पर्यटन एवं उद्योग क्षेत्रों से जुड़ी विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं के माध्यम से लोगों को रोजगार एवं स्वरोजगार से जोड़ने की दिशा में विशेष ध्यान दिया जाए। 'जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार' अभियान के माध्यम से लोगों को इन योजनाओं की संपूर्ण जानकारी प्रदान की जाए, ताकि वे इनका लाभ उठा सकें।मुख्यमंत्री ने युवाओं के कौशल विकास पर विशेष ध्यान देने तथा उन्हें स्वरोजगार के लिए अधिकतम अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में प्रभावी कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पात्र लोगों को योजनाओं का समय पर एवं पूरा लाभ मिले, इस पर सभी विभाग विशेष ध्यान दें। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि आवंटित बजट का पूर्ण आउटकम प्राप्त हो।मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि उच्च स्तरीय बैठकों के कार्यवृत्त उन्नति पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपलोड किए जाएं। उन्होंने सेब की अति सघन बागवानी योजना की समीक्षा करते हुए कहा कि इस महत्वाकांक्षी योजना को प्रभावी ढंग से संचालित कर निर्धारित लक्ष्यों को समय से प्राप्त किया जाए तथा किसानों को अधिकाधिक प्रोत्साहन प्रदान किया जाए। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि किसानों से संबंधित देयकों का भुगतान समय पर हो। किसानों को उनके उत्पादन का बेहतर मूल्य मिले, इसके लिए राज्य में कीवी उत्पादन को बढ़ावा देने की दिशा में तेजी से कार्य किया जाए।मुख्यमंत्री ने कहा कि शहद उत्पादन के क्षेत्र में उत्तराखंड में व्यापक संभावनाएं हैं। इसे देखते हुए 'हनी मिशन' के अंतर्गत शहद उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए और अधिक प्रभावी प्रयास किए जाएं। राज्य में शहद का ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि बागवानी एवं मौन पालन के क्षेत्र में जिन राज्यों में अच्छा कार्य हुआ है, उनके अध्ययन हेतु अधिकारियों एवं विशेषज्ञों की टीमें उन राज्यों में भेजी जाएं।बैठक में जानकारी दी गई कि प्रदेश के 29 उत्पादों को जी.आई. टैग प्राप्त हुआ है, जिनमें से 18 कृषि एवं कृषि कल्याण से संबंधित हैं। इस वर्ष 25 अन्य उत्पादों को जी.आई. टैग के लिए चिन्हित किया जाएगा। राज्य में 134 करोड़ रुपये की लागत से लागू स्टेट मिलेट पॉलिसी के अंतर्गत मंडुवा, झंगोरा, रामदाना, कौणी एवं चीना को शामिल किया गया है। इसके अंतर्गत प्रथम चरण में 30 हजार हेक्टेयर क्षेत्रफल के 24 विकासखंडों तथा द्वितीय चरण में 40 हजार हेक्टेयर क्षेत्रफल के 44 विकासखंडों का चयन किया गया है। प्रथम चरण में 5 हजार से अधिक गांवों को आच्छादित कर लगभग डेढ़ लाख कृषकों को लाभान्वित किया गया है। मिलेट फसलों की क्रय-विक्रय हेतु 216 क्रय केंद्र खोले गए हैं तथा सहकारिता विभाग के अंतर्गत 20 करोड़ रुपये का रिवाल्विंग फंड बनाया गया है। इस वित्तीय वर्ष में 5 हजार मीट्रिक टन के लक्ष्य के सापेक्ष अब तक 5,386 मीट्रिक टन मिलेट फसलों का क्रय किया जा चुका है।बैठक में यह भी जानकारी दी गई कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना एवं मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2.0 के अंतर्गत चार वर्षों में 32 हजार के लक्ष्य के सापेक्ष 33,620 लाभार्थियों को 202.72 करोड़ रुपये की धनराशि उपलब्ध कराई गई है। आगामी वर्ष में 9 हजार लोगों को लाभान्वित किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। पर्यटन विभाग के अंतर्गत दीन दयाल उपाध्याय होम स्टे योजना के तहत चार वर्षों में 780 होम स्टे स्थापित किए गए हैं, जिसके लिए 188.58 करोड़ रुपये का वित्त पोषण किया गया है। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना के अंतर्गत चार वर्षों में एक हजार से अधिक लोगों को लाभान्वित किया गया है, जिसमें कुल 105 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि का वित्त पोषण किया गया है। राज्य में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत मत्स्य पालन क्षेत्र में 17,450 लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त हुआ है।बैठक में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, गणेश जोशी, प्रमुख सचिव डॉ. आर. मीनाक्षी सुंदरम, सचिव नितेश झा,दिलीप जावलकर, विनय शंकर पाण्डेय, एस.एन. पाण्डेय, वी. षणमुगम, धीराज गर्ब्याल सहित संबंधित विभागों के उच्च अधिकारी उपस्थित रहे।

उत्तराखंड को विमानन क्षेत्र में मिला सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार

देहरादून (उद संवाददाता)। हैदराबाद में आयोजित अंतरराष्ट्रीय विमानन सम्मेलन एवं प्रदर्शनी विंग्स इंडिया 2026 में उत्तराखंड ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। राज्य को नागरिक उड्डयन क्षेत्र में किए गए प्रभावी प्रयासों और नीतिगत सुधारों के लिए 'बेस्ट स्टेट फॉर प्रमोशन ऑफ एविएशन इकोसिस्टम' के प्रतिष्ठित पुरस्कार से नवाजा गया है। यह सम्मान प्रदेश में विमानन पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने और हवाई सेवाओं के विस्तार के लिए राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का परिणाम माना जा रहा है। हैदराबाद के बेगमपेट एयरपोर्ट पर आयोजित एक भव्य समारोह के दौरान केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापु राममोहन नायडू और नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सचिव समीर कुमार सिन्हा ने यह पुरस्कार प्रदान किया। उत्तराखंड की ओर से इस गौरवशाली क्षण का हिस्सा बनने के लिए नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण (यूकाडा) के सचिव सचिन कुर्वे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. आशीष चौहान, अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय सिंह टोलिया और हेड ऑफ ऑपरेशंस कैप्टन अमित शर्मा कार्यक्रम में मौजूद रहे। विंग्स इंडिया 2026 देश का एक प्रमुख विमानन मंच है जहां दुनिया भर के नीति निर्माता, निवेशक और उद्योग जगत के विशेषज्ञ जुटते हैं। इस महत्वपूर्ण उपलब्धि पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि यह पुरस्कार उत्तराखंड की समग्र विमानन नीति और बेहतर प्रशासनिक समन्वय का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि पर्वतीय और दूरस्थ क्षेत्रों को हवाई सेवाओं से जोड़ना सरकार की प्राथमिकता रही है जिससे पर्यटन के साथ-साथ आपदा प्रबंधन और स्वास्थ्य सेवाओं में भी बड़ा सुधार हुआ है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और केंद्र के सहयोग से प्रदेश में उड़ान योजना का सफल क्रियान्वयन हो रहा है और आधुनिक बुनियादी ढांचे के विकास से उत्तराखंड तेजी से एक उभरते विमानन हब के रूप में स्थापित हो रहा है। इस सम्मान से भविष्य में राज्य के भीतर निवेश और विकास के नए रास्ते खुलने की उम्मीद है।

मुख्यमंत्री ने 'लैब ऑन व्हील्स' को किया रवाना

छात्र अब वैन में सीखेंगे एआई और कोडिंग

देहरादून (उद संवाददाता)। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय से छात्रों के कौशल विकास के लिए 'लैब ऑन व्हील्स' (इंफोसिस स्प्रिंगबोर्ड) को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह मोबाइल लैब राज्य के छात्रों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), कोडिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी) और अन्य उभरते तकनीकी क्षेत्रों में व्यावहारिक प्रशिक्षण यानी हैंड्स-ऑन सुविधा उपलब्ध कराएगी। इसके माध्यम से छात्र विज्ञान के विभिन्न प्रयोगों को वर्चुअल मोड में भी सीख सकेंगे।यह अनूठी पहल छात्रों को 'लर्निंग बाई डूइंग' (करके सीखना) के लिए एक आधुनिक मंच प्रदान करेगी। इंफोसिस स्प्रिंगबोर्ड लैब ऑन व्हील्स अगले पांच वर्षों तक राज्य के विभिन्न शिक्षण संस्थानों में जाएगी और विद्यार्थियों को जागरूक करने के साथ-साथ उन्हें वैश्विक स्तर की तकनीकी संभावनाओं से जोड़ेगी। राज्य में प्रयोगात्मक प्रशिक्षण की कमी को दूर करने में यह लैब मील का पत्थर साबित होगी। यह सुविधा उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और विद्यालयी शिक्षा ग्रहण कर रहे सभी छात्रों के लिए समान रूप से उपयोगी रहेगी। इस अवसर पर विधायक सविता कपूर, प्रमोद नैनवाल, उच्च शिक्षा उन्नयन समिति के उपाध्यक्ष डॉ. देवेन्द्र भसीन, डॉ. जयपाल सिंह चौहान, सचिव उच्च शिक्षा डॉ. रंजीत कुमार सिन्हा सहित उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा विभाग के अधिकारी एवं इंफोसिस के प्रतिनिधि मौजूद रहे। मोबाइल लैब के माध्यम से दूरस्थ क्षेत्रों के छात्रों को भी अब अत्याधुनिक तकनीक से रूबरू होने का मौका मिलेगा।

नैनीताल में कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर प्रशिक्षण शुरू

नैनीताल (उद संवाददाता)। डॉ. आर.एस. टोलिया उत्तराखंड प्रशासन अकादमी में राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस प्रभाग (एनईजीडी) और भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सहयोग से तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। 'कृत्रिम बुद्धिमत्ता के माध्यम से ई-गवर्नेंस' विषय पर आधारित इस कार्यक्रम का उद्घाटन अकादमी के महानिदेशक बी. पी. पाण्डेय ने किया। 29 से 31 जनवरी तक चलने वाले इस शिविर में देश के विभिन्न राज्यों और विभागों के 30 वरिष्ठ अधिकारी हिस्सा ले रहे हैं। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम अकादमी और एनईजीडी द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित अपनी तरह की पहली पहल है। प्रशिक्षण के दौरान अधिकारियों को एआई की मूल अवधारणाओं, स्मार्ट और उत्तरदायी शासन में एआई की भूमिका, जेनरेटिव एआई और शासन में जिम्मेदार एआई के क्रियान्वयन से जुड़ी चुनौतियों जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारी दी जा रही है। साथ ही प्रतिभागियों को विभिन्न एआई टूल्स पर व्यावहारिक (हैंड्स-ऑन) प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा। उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए महानिदेशक बी.पी. पाण्डेय ने शासन व्यवस्था में एआई के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि एआई के माध्यम से सरकारी सेवाओं को अधिक तेज, कुशल, पारदर्शी और डेटा आधारित बनाया जा सकता है, जिसका सीधा लाभ आम नागरिकों को मिलेगा। उन्होंने एआई के नैतिक, मानवीय और भावनात्मक मूल्यों से जुड़ी चुनौतियों पर भी चर्चा की और इसके संतुलित उपयोग पर बल दिया। उन्होंने अधिकारियों से अपने-अपने विभागों में एआई के संभावित उपयोग वाले क्षेत्रों की पहचान करने का आह्वान किया ताकि शासकीय प्रक्रियाओं को सुगम बनाया जा सके। इस कार्यक्रम में प्रतिष्ठित संस्थानों के तकनीकी विशेषज्ञों और निजी क्षेत्र के पेशेवरों को व्याख्यान के लिए आमंत्रित किया गया है। उद्घाटन सत्र में संयुक्त निदेशक डॉ. महेश कुमार, उप निदेशक वी.के. सिंह और कार्यक्रम निदेशक बिकास के. नायक भी उपस्थित रहे। यह पहल शासन में नवाचार और तकनीकी दक्षता को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है।

प्रदेश में शुरू होगी पेयजल की जैविक जांच

देहरादून। उत्तराखंड की नदियों, गाड-गदेरों में खतरनाक बैक्टीरिया, वायरस, कवक और परजीवी पनप रहे हैं। बैक्टीरिया जनित यह पानी लोगों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा है। इंदौर में पिछले दिनों सामने आई दूषित पेयजल से मौतों जैसी घटना से बचाव के लिए जल संस्थान की 27 लैब में अब पेयजल की माइक्रोबायोलॉजी जांच शुरू होने जा रही है। इसके उपकरणों की खरीद के लिए शासन ने बजट जारी कर दिया है। प्रदेश में जल संस्थान की 13 जिलास्तरीय, एक राज्यस्तरीय और 13 उपखंडीय लैब है। ये सभी लैब नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लैबोरेटरीज (एनएबीएल) से मान्य हैं। लेकिन इनको अभी तक पानी की फिजियो केमिकल (पीएच, टीडीएस, क्लोराइड, फ्लोराइड, आयरन आदि) जांच के लिए ही मान्यता मिली है, माइक्रोबायोलॉजी जांच के लिए नहीं। जल संस्थान ने इसकी कवायद शुरू कर दी है। शासन ने एनएबीएल से माइक्रोबायोलॉजी जांच की मान्यता के लिए 192 लाख रुपये जारी किए हैं। इस बजट से लैबों में बायोसेफ्टी कैबिनेट, इंक्यूबेटर, ऑटोक्लेव, मेंब्रेन फिल्ट्रेशन असेंबली, कॉलोनी काउंटर, सूक्ष्मदर्शी और तुला जैसे जरूरी उपकरण खरीदे जाएंगे। इसके बाद पेयजल की सभी लैब में माइक्रोबायोलॉजी जांच भी शुरू हो जाएगी।

सरकार ने मंत्रियों का यात्रा भत्ता प्रतिमाह 30 हजार रुपये बढ़ाया

देहरादून। प्रदेश सरकार ने मंत्रियों का यात्रा भत्ता में प्रति माह 30 हजार रुपये बढ़ा दिया है। इस संबंध में शासन ने अधिसूचना जारी कर दी है। अब मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों, राज्य मंत्री व उप मंत्रियों को भारत में यात्रा करने पर प्रतिमाह अधिकतम 90 हजार रुपये मिलेंगे। सचिव शैलेश बगौली के आदेश से मंत्रिपरिषद अनुभाग ने यात्रा भत्ता बढ़ाने की अधिसूचना जारी कर दी है। इसके अनुसार अभी तक मंत्रियों को यात्रा भत्ता 60 हजार रुपये मिलता था, इसे बढ़ाकर अधिकतम 90 हजार रुपये प्रति माह कर दिया गया है।यात्रा भत्ता बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश मंत्री (यात्रा भत्ता) नियमावली 1997 में संशोधन किया गया है, जिसे अब उत्तर प्रदेश मंत्री (यात्रा भत्ता) (संशोधन) नियमावली 2026 के रूप में लागू किया गया है। इस संशोधन के तहत नियम चार में बदलाव करते हुए मंत्रियों के यात्रा भत्ते की अधिकतम सीमा बढ़ाई गई है। बता दें कि वर्ष 2024 में सरकार ने विधायकों के वेतन व भत्तों में बढ़ोतरी की थी।

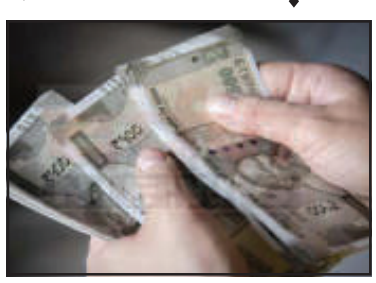

नवोदय विद्यालय में सुविधओं को लेकर सीडीओ ने दिए दिशा निर्देश

जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रबंधन समिति की बैठक आयोजित

रूद्रपुर(उद संवाददाता)।जवाहर नवोदय विद्यालय सभागार में मुख्य विकास अधिकारी देवेश शाशनी जी की अध्यक्षता में विद्यालय प्रबंधन समिति एवं विद्यालय सलाहकार समिति की बैठक का आयोजन हुई। बैठक के दौरान विद्यालय की शैक्षणिक, खेलकूद एवं सह- पाठ्यक्रम गतिविधियों से संबंधित उपलब्धियों पर विस्तार से प्रधानाचार्य ने अवगत कराया। विद्यार्थियों के बोर्ड परीक्षाओं एवं प्रतियोगी परीक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन, अनुशासनात्मक वातावरण तथा नवाचार आधारित शिक्षण प्रयासों को समिति द्वारा सराहना की गयी। प्रधानाचार्य ने विद्यालय की भूमि का स्थाई हस्तान्तरण कराने का अनुरोध किया। जिसपर मुख्य विकास अधिकारी ने प्रशासन स्तर पर शीघ्र आवश्यक कार्रवाई कराने का आश्वासन दिया। मुख्य विकास अधिकारी ने विद्यालय परिसर एवं आसपास के क्षेत्रों में नियमित फॉगिंग कराने के निर्देश नगर आयुक्त को दिये। उन्होने विद्यालय गेट व वॉउंड्री वॉल के पास

सीसी टीवी कैमरा लगाने के निर्देश दिये ताकि वॉउंड्री के पास कूड़ा डालने वालों को चिन्हित कर कार्यवाही की जा सकें। प्रधानाचार्य ने बताया कि उरेडा विभाग के माध्यम से भोजनालय व छात्रावास में गरम पानी हेतु सोलर गीजर की स्थापना करायी गयी थी जो काफी दिनो से खराब है। जिसपर मुख्य विकास अधिकारी ने परियोजना अधिकारी उरेडा को सोलर गीजर का परीक्षण कराकर ठीक कराने के निर्देश दिये। उन्होने मुख्य चिकित्साधिकारी को समय-समय पर विद्यालय में चिकित्सकों की टीम भेज कर छात्रों के स्वास्थ्य परीक्षण कराने व दवाई देने के भी निर्देश दिये। उन्होने जेईई/नीट जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए विशेष शैक्षणिक सहयोग उपलब्ध कराने, विद्यालय हित में तीन आरओ वाटर प्यूरीफायर प्रदान कराने तथा गैस पाइपलाइन सुविधा हेतु प्रशासनिक सहयोग देने का आश्वासन दिया। उन्होंने बेहतर शैक्षणिक परिणाम सुनिश्चित करने के लिए हर स्तर पर सहयोग प्रदान करने की प्रतिबद्धता जताते हुए विद्यालय परिवार को और अधिक परिश्रम के साथ विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य निर्माण हेतु कार्य करने के निर्देश दिये। सांसद प्रतिनिधि अभिनव चौधरी ने विद्यालय को एक नई रोटी मेकिंग मशीन उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया, जिससे भोजन व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाया जा सकेगा। बैठक में उपस्थित अधिकारियों एवं शिक्षकों ने विद्यालय के सर्वांगीण विकास, स्वच्छ एवं सुरक्षित वातावरण निर्माण तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु समन्वित प्रयासों पर बल दिया।बैठक में मुख्य शिक्षा अधिकारी के एस रावत, प्रधानाचार्य कंचन जोशी, एसीएमओ डॉ0 एसपी सिंह, परियोजना अधिकारी उरेडा संदीप सैनी, उप प्राचार्य पी.के. विद्यार्थी, रमेश चंद्र गौर, मोहन चंद्र सुयाल, कृष्ण पाल, अनुराग शर्मा, संजीव सिंह आदि भी उपस्थित थे।

विधायक बेहड़ ने जाना ठुकराल की मां का हाल

रूद्रपुर (उद संवाददाता)। किच्छा के विधायक तिलकराज बेहड़ ने गुरूवार को उपचार के लिए निजी चिकित्सालय में भर्ती पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल की माता का हाल जानने के लिए पहुंचे। जहां उन्होंने श्री ठुकराल से माता का हाल जाना और चिकित्सकों से बातचीत की। श्री ठुकराल ने बताया कि उनके ऊपर मुकदमा दर्ज होने की जानकारी मिलते ही माता की तबीयत बिगड़ गई थी। उन्होंने बताया एक साल पूर्व उनका कथित वीडियों वायरल हुआ था। जिसके बाद उनकी

माता ने स्वयं पूर्व पालिकाध्यक्ष मीना शर्मा के घर जाकर माफी मागी थी। अब फिर उसी मामले में उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करा दिया गया। किसी ने इसकी जानकारी उनकी माता को दे दी। जिसके बाद उनकी माता की तबीयत बिगड़ गई और उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। ठुकराल ने बताया कि बुधवार को वह स्वयं भी सार्वजनिक रूप से मीना शर्मा से माफी मांग चुके हैं। विधायक श्री बेहड़ ने ठुकराल की माता के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की।

किसान मोर्चा प्रदेश महामंत्री का व्यापारियों ने किया जोरदार स्वागत

गूलरभोज। व्यापार मंडल अध्यक्ष डॉ. कुलदीप रघुवंशी के प्रतिष्ठान पर किसान मोर्चा के प्रदेश महामंत्री नरेश हुंडिया के प्रथम आगमन पर व्यापारियों ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान व्यापारियों ने माला पहनाकर और मिठाई बांटकर अपनी खुशी का इजहार किया।इस अवसर पर व्यापारी हितों और क्षेत्रीय विकास को लेकर

भी अनौपचारिक चर्चा हुई। स्वागत कार्यक्रम में मुख्य रूप से सतीश सिडाना, रामकिशन दहूजा, अजय अरोड़ा, अमित गुप्ता, प्रीत बठला, शिवम रघुवंशी, प्रथम ठुकराल, कीर्तीलाल और सौरभ सहित अनेक व्यापारी उपस्थित रहे। प्रदेश महामंत्री ने व्यापारियों के उत्साह और स्वागत के लिए सभी का आभार व्यक्त किया।

ऊर्जा निगम के एसडीओ गुरुरानी को मिला उत्कृष्ट सेवा सम्मान

किच्छा।गणतंत्र दिवस पर ऊर्जा निगम के उपखंड अधिकारी दिनेश चंद्र गुरुरानी को उत्कृष्ट सेवा के लिए प्रशस्ती पत्र देकर सम्मानित किया गया। गुरुरानी को विभाग ने उनकी बेहतर सेवाओं के लिए लगातार 14वीं बार सम्मानित किया है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर देहरादून में आयोजित समारोह में ऊर्जा निगम के एमडी अनिल यादव ने दिनेश गुरुरानी को प्रशस्ती पत्र देकर सम्मानित किया। किच्छा विद्युत वितरण उपखंड में एसडीओ के पद पर कार्यरत दिनेश चंद्र गुरुरानी चार वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहे है। गुरुरानी की उपलब्धियों में मुख्य रुप से बिजली चोरी के खिलाफ अभियान चलाना रहा है।इसके अंतर्गत उन्होंने आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही करते हुए क्षेत्र में बिजली चोरी को रोकने में अपना अहम योगदान दिया है। गुरुरानी ने किच्छा

एवं पंतनगर क्षेत्र में रोड किनारे लगे ट्रांसफार्मरों को लोहे के बाउंड्री से कवर कर दुर्घटनाओं को रोकने की दिशा में कार्य किया। गुरुरानी के निर्देशन में 33 एवं 11केवी के जर्जर तारों को बदल कर नये बंद तारों की विद्युत लाइन बिछाई गयी । जिससे तार टूटने अथवा उनसे होने वाली दुर्घटनाओं पर विराम लगा है। पावर हाउस एवं लाइनों पर लगे ट्रांसफार्मरों को बदल कर उनकी क्षमता बढ़ाई गई। जिससे उपभोक्ताओं को कम वोल्टेज की समस्या से निजात मिली है। विद्युत वितरण उपखंड ने 70 प्रतिशत स्मार्ट मीटर लगा कर बड़ी सफलता हासिल की है। दिनेश चंद्र गुरुरानी की बेहतर जनसुनवाई व कार्य शैली के लिए स्थानीय संगठन पूर्व में सम्मानित कई बार सम्मानित कर चुके है। चुनिंदा अधिकारियों में लगातार 14 वीं बार सम्मानित किया जाने पर एसडीओं गुरुरानी ने गौरव का पल बताया। उन्होंने कहा कि विद्युत विभाग का पहला कार्य प्रत्येक उपभोक्ता को विद्युत उपलब्ध कराना है जिसके लिए सभी आवश्यक कार्य किए जाने होते हैं उन्होंने कहा कि विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा लगातार सहयोग दिए जाने के चलते विद्युत उपखंड में विद्युत वितरण व्यवस्था सुदृढ़ बना पाई है। उन्होंने कहा कि आगे भी वे अपने कार्यकाल में विद्युत वितरण उपखंड के अंतर्गत आने वाले सभी उपभोक्ताओं को विद्युत सप्लाई विद्युत व्यवस्था विद्युत से संबंधित सभी समस्याओं का निराकरण करते रहेंगे तथा ऊर्जा निगम को भी ऊंचाइयों पर ले जाने का कार्य करेंगे।

करंट की चपेट में आने से दुधारू गाय की मौत

गूलरभोज। रेलवे फाटक के समीप खोखे में करंट उतरने से उसकी चपेट में आकर एक दुधारू गाय की मौके पर ही मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार, वन विभाग से सेवानिवृत्त ड्राइवर बहादुर राम बृहस्पतिवार दोपहर अपनी गाय को चराने के लिए ले जा रहे थे। इसी दौरान रेलवे फाटक के पास स्थित एक लोहे के खोखे से टकराते ही गाय करंट की चपेट में आ गई और उसने तड़प-तड़प कर दम तोड़ दिया। पीड़ित बहादुर राम ने घटना की सूचना पशु चिकित्सालय को दे दी है। अचानक हुई इस घटना से पशुपालक को काफी आर्थिक नुकसान पहुंचा है।

पीएमएस संघ के डा.सरना अध्यक्ष व डा. गंगवार सचिव बने

रुद्रपुर। प्रांतीय चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा संघ (पीएमएस संघ) की नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। जिसमें

डॉ. संजीव सरना अध्यक्ष, डॉ. अतुल कुमार उपाध्यक्ष (क्षेत्र), डॉ. राजेश आर्य उपाध्यक्ष (मुख्यालय), डॉ. तनुजा सिन्हा उपाध्यक्ष (महिला), और डॉ. सुनील उपाध्याय उपाध्यक्ष (डेंटल) चुने गए। निर्वाचित नई कार्यकारिणी में डॉ. आशीष गंगवार सचिव, डॉ. एस पी. सिंह कोषाध्यक्ष, डॉ. डी.एम. गहलोत केंद्रीय प्रतिनिधि चुने गए हैं। मीडिया प्रभारी डॉ. डी. पी. सिंह, उप सचिव डॉ. अमरजीत सिंह और संगठक डॉ. पी. डी. गुप्ता हैं। नव निर्वाचित पदाधिकारियों को शुभकामनाएं देते हुए, उपस्थित चिकित्सकों ने आशा व्यक्त की कि नई कार्यकारिणी चिकित्सकों के हितों की रक्षा, संगठन की एकता, और स्वास्थ्य सेवाओं की मजबूती के लिए सक्रिय भूमिका निभाएगी। बैठक में नई कार्यकारिणी के लक्ष्य भी निर्धारित किए गए जिसमें चिकित्सकों के हितों की रक्षा करना, संगठन की एकता और मजबूती के लिए काम करना, स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करना, चिकित्सकों की सुरक्षा और सम्मान के लिए काम करना और जनहित से जुड़े मुद्दों पर संगठित प्रयास करना है।

निजी विद्यालयों में फीस वृद्धि के खिलाफ बीईओ को घेरा

सितारगंज। क्षेत्र के अनेक निजी विद्यालयों में बच्चों से ली जाने वाली मासिक फीस में की गई वृद्धि के खिलाफ भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ पूर्व छात्र संघ पदाधिकारियों ने खंड शिक्षा अधिकारी का घेराव कर उन्हें ज्ञापन सौंपा। उनका कहना था कि निजी स्कूल प्रबंधन अभिभावकों पर एडवांस फीस जमा करवाने को दबाव डाल रहे हैं। साथ ही समय से फीस जमा न होने पर अतिरिक्त शुल्क के साथ बोर्ड परीक्षओं में छात्र को न बैठने की धमकी दे रहे हैं। इस सन्दर्भ में स्कूल प्रबंधन से बातचीत का कोई हल नहीं निकला। पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष गणेश ठकुराठी ने कहा कि स्वयं उनके पुत्र को इस उत्पीड़न का शिकार होना पड़ा है। भाजपा पूर्व नगर मंडल महामंत्री मनोज वाधवा ने कहा कि जो निजी विद्यालय अभिभावकोंका शोषण कर रहे हैंउनकी मान्यता रद्द कर देनी चाहिए। खण्ड शिक्षा अधिकारी भानु प्रकाश कुशवाहा ने कहा कि मामले की जांच कर कार्रवाई की जायेगी। घेराव करने वालों में किशोर जोशी, सतीश भट्ट, नीरज रस्तोगी, दीपक सावंत, भुवन जोशी, करण यादव आदि शामिल थे।

दानपुर बाजार से बाइक चोरी

रूद्रपुर (उद संवाददाता)। कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत दानपुर बाजार से एक व्यक्ति की बाइक अज्ञात चोरों ने पार कर दी। काफी खोजबीन के बाद भी जब वाहन का पता नहीं चला, तो पीड़ित ने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है।प्राप्त जानकारी के अनुसार, सुनील कुमार पुत्र भोले राम, निवासी ग्राम दियोरनिया अमरिया, जिला पीलीभीत ने पुलिस को बताया कि वह बीते दिनों अपनी बाइक संख्या यूपी 26एडब्लू 2017 से दानपुर बाजार गया था। उसने अपनी स्प्लेंडर प्लस बाइक को सड़क किनारे लॉक करके खड़ा किया था और बाजार करने चला गया। कुछ समय बाद जब वह वापस लौटा, तो उसकी बाइक मौके से नदारद थी।सुनील कुमार ने आस-पड़ोस के लोगों से पूछताछ की और काफी देर तक आसपास के इलाकों में बाइक की तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं लग सका। अज्ञात चोर द्वारा बाइक चोरी कर लिए जाने के बाद पीड़ित ने कोतवाली रूद्रपुर में लिखित शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने तहरीर के आधार पर अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। पुलिस अब बाजार क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है ताकि चोरों की पहचान की जा सके।

कैंची धाम में सफाई और निर्माण कार्यों को लेकर प्रभारी डीएम सख्त

हल्द्वानी। प्रभारी जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी अरविंद कुमार पाण्डे ने हल्द्वानी कैंप कार्यालय में श्री कैंची धाम से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों पर अधिकारियों की बैठक ली। एनजीटी में योजित याचिका के अनुपालन में आयोजित इस बैठक में मुख्य रूप से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी), साफ-सफाई और अवैध निर्माण कार्यों की समीक्षा की गई। बैठक के दौरान प्रभारी जिलाधिकारी ने पेयजल निगम के अधिशासी अभियंता को निर्देशित किया कि कैंची धाम में एसटीपी के प्रस्ताव पर तय समय सीमा के भीतर अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। उन्होंने धार्मिक स्थल की संवेदनशीलता और पर्यावरण संरक्षण को देखते हुए इस कार्य में तेजी लाने पर जोर दिया। इसके साथ ही जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण के सचिव को कैंची धाम क्षेत्र में बढ़ते निर्माण

कार्यों को सुनियोजित करने, नियमों के विरुद्ध हो रहे निर्माण पर चालानी कार्रवाई करने और संबंधित मामलों का समय पर निस्तारण करने के निर्देश दिए। साफ-सफाई की व्यवस्थाओं को लेकर उन्होंने नगर पालिका भवाली के अधिशासी अधिकारी और जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी को स्पष्ट निर्देश दिए कि कैंची धाम में नियमित स्वच्छता अभियान चलाया जाए। उन्होंने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट (ठोस अपशिष्ट प्रबंधन) के लिए प्रभावी कार्ययोजना बनाने और कूड़ा निस्तारण हेतु आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने को कहा। बैठक में उपजिलाधिकारी कैंची धाम मोनिका, सचिव जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण विजयनाथ शुक्ल, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका भवाली और अधिशासी अभियंता पेयजल निगम सहित अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।

उत्तरांचल दर्पण सम्पादकीय

सत्यम् शिवम् सुन्दरम्

देश की अर्थव्यवस्था

हर साल संसद में पेश होने वाली आर्थिक समीक्षा आमतौर पर इस बात का ब्योरा होती है कि पिछले बजट में देश की अर्थव्यवस्था और अन्य मोर्चे पर सुधार के लिए जो वादे किए गए थे, वे किस हद तक पूरे किए जा सके। यह इसका भी संकेत होता है कि अगले वित्त वर्ष में सरकार के आर्थिक फैसलों में किन मसलों को प्राथमिकता मिल सकती है। इस लिहाज से देखें, तो वित्त मंत्री ने जो आर्थिक समीक्षा पेश की है, वह देश की परिस्थितियों और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खड़ी हो रही आर्थिक चुनौतियों के बीच उम्मीद जगाती है, लेकिन यह आने वाले वक्त के जोखिमों के प्रति आगाह भी करती है। समीक्षा में वित्त वर्ष 2026-27 में सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 6.8 फीसद से 7.2 फीसद के बीच रहने का अनुमान जताया गया है। विदेशी पूंजी प्रवाह में कमी के कारण रुपए पर प्रतिकूल असर और बीते वर्ष भारतीय मुद्रा में कमजोरी के बावजूद यह अनुमान अर्थव्यवस्था में स्थिरता का संकेत देता है। हालांकि समीक्षा में विकसित भारत और वैश्विक प्रभाव का लक्ष्य हासिल करने के उद्देश्य से मजबूत और स्थिर मुद्रा को एक स्वाभाविक जरूरत बताने के समांतर रुपए के मूल्य में गिरावट को हानिकारक नहीं माना गया, क्योंकि यह भारतीय वस्तुओं पर अमेरिकी शुल्क में इजाफे के असर को कुछ हद तक कम करता है। दूसरी ओर, यूरोप के साथ मुक्त व्यापार समझौते को लेकर यह उम्मीद जताई गई है कि यह भारत की विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मक, निर्यात और रणनीतिक क्षमता को मजबूत करेगा। समीक्षा के मुताबिक, अनिश्चित वैश्विक माहौल में भारत को घरेलू वृद्धि को प्राथमिकता देने की जरूरत है और इसके लिए वित्तीय सुरक्षा उपायों और नकदी पर ज्यादा जोर देना चाहिए। आर्थिक समीक्षा में नवोन्मेष और वैश्विक पहलकदमियों को कमजोर किए बिना दक्षता और स्वदेशी को अपनाने का आह्वान किया गया है, जो निश्चित रूप से आत्मनिर्भरता की संभावनाओं को मजबूत करेगा। कृषि क्षेत्र देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ रहा है। इस बिंदु पर सर्वेक्षण में यह कहा गया है कि कृषि निर्यात में व्यापार नीति का उपयोग कीमतों और उत्पादन में अस्थिरता के बीच अल्पकालिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किया जाता है। मगर बार-बार नीतिगत बदलाव आपूर्ति शृंखला को बाधित करते हैं। यह देखने की बात होगी कि समीक्षा में जाहिर इस चिंता के संदर्भ में बजट की क्या दिशा होती है। यों, महंगाई का असर नरम रहने और अगले वर्ष भी चिंता का बड़ा कारण नहीं बनने को लेकर उम्मीद जताई गई है। समीक्षा में अस्थायी कामगारों के लिए काम से जुड़ी शर्तें नए सिरे से तय करने के उद्देश्य से नीति लाने की जरूरत पर जोर दिया गया है। इसके अलावा, नागरिकों की सेहत की सुरक्षा के मद्देनजर अधिक वसा और चीनी वाले अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों की बढ़ती खपत पर चिंता जताई गई है और इन उत्पादों के विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाने का सुझाव भी दिया गया है। आर्थिक समीक्षा में कई राज्यों में लोकलुभावन घोषणाओं और नकद अंतरण के कारण राजस्व घाटा बढ़ने को लेकर भी चिंता जताई गई।

उत्तराखण्ड में नए शहरों और टाउनशिप के विकास पर हुई विस्तृत चर्चा

देहरादून। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 'विकसित भारत 2047' के संकल्प को साकार करने और मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखण्ड को सुनियोजित, आधुनिक एवं समावेशी राज्य के रूप में विकसित करने की दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य में सभी के लिए आवास, नए नगरों के विकास और शहरी-ग्रामीण क्षेत्रों में संतुलित विस्तार को गति देने के उद्देश्य से आज हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (हडको) के सहयोग से संचालित योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की गई। सचिव आवास डॉ. आर. राजेश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना, रेंटल हाउसिंग योजना एवं भविष्य की शहरी विकास रणनीतियों पर गहन विचार-विमर्श किया गया। इस बैठक का मुख्य फोकस राज्य में आवासीय जरूरतों को दीर्घकालिक दृष्टि से पूरा करना, विशेषकर ईडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) और एलआईजी (निम्न आय वर्ग) के लिए सस्ते, सुरक्षित और टिकाऊ आवास उपलब्ध कराना रहा।बैठक में इस बात पर सहमति बनी कि उत्तराखण्ड की भौगोलिक, सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए 2047 के विकसित भारत लक्ष्य और 2050 तक की आवासीय जरूरतों के लिए एक समग्र एवं व्यावहारिक कार्ययोजना तैयार की

जाए। इसमें शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में सुनियोजित निर्माण, आधारभूत सुविधाओं का विस्तार और भविष्य के नए नगरों की परिकल्पना शामिल होगी।हडको के क्षेत्रीय प्रमुख एवं राज्य प्रभारी संजय भार्गव ने राज्य सरकार को आश्वस्त किया कि उत्तराखण्ड में नए शहरों और टाउनशिप के विकास, भूमि अधिग्रहण, मास्टर प्लानिंग और वित्तीय सहयोग में हडको अपनी विशेषज्ञता और अनुभव का पूरा लाभ राज्य को देगा। बैठक में इस बात पर विशेष जोर दिया गया कि आवासीय योजनाएं केवल शहरों तक सीमित न रहें, बल्कि ग्रामीण और पर्वतीय क्षेत्रों में भी सुनियोजित ढंग से लागू हों। इससे पलायन की समस्या को कम करने, स्थानीय रोजगार सृजन और क्षेत्रीय संतुलन को मजबूती मिलेगी। उत्तराखण्ड के 10 पर्वतीय जिलों में स्थानीय भवन तकनीक और पारंपरिक निर्माण सामग्री के अधिकतम उपयोग पर विशेष ध्यान देने का निर्णय लिया गया। इससे जहां निर्माण लागत कम होगी, वहीं राज्य की सांस्कृतिक विरासत और पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा। साथ ही भवन स्वीकृति प्रक्रिया को सरल बनाने और सस्ते आवास निर्माण के लिए नवाचारों को अपनाने पर सहमति बनी।प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ-साथ रेंटल आवास योजना को भी गति देने पर चर्चा हुई, जिससे प्रवासी श्रमिकों, युवाओं और कामकाजी वर्ग को सुरक्षित एवं किफायती आवास उपलब्ध कराया जा सके। यह कदम शहरी क्षेत्रों में अनियोजित बसावट को रोकने में भी सहायक होगा।बैठक में जानकारी दी गई कि हडको देहरादून द्वारा राज्य में अब तक 1543.34 करोड़ रुपये की ऋण राशि वाली 115 आवासीय एवं शहरी विकास योजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है। राज्य सरकार और हडको के संयुक्त प्रयासों से राज्य में आवास की उपलब्धता बढ़ेगी, ईडब्ल्यूएस और एलआईजी वर्ग को सम्मानजनक जीवन मिलेगा और उत्तराखण्ड आधुनिक, टिकाऊ और समावेशी विकास की दिशा में तेजी से आगे बढ़ेगा।

हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर में कोहरे का यलो अलर्ट

देहरादून। लंबे इंतजार के बाद उत्तराखंड में बारिश-बर्फबारी हुई तो लोगों के चेहरे खुशी से खिल उठे लेकिन अब पहाड़ी इलाकों में शीतलहर और मैदानी क्षेत्रों में कोहरा छाने से ठंड परेशान करने लगी है। हालांकि दिन में चटक धूप खिलने से मौसम सुहाना हो रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से शुक्रवार को हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर जिले में कोहरा छाने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं, देहरादून, पौड़ी, हरिद्वार, नैनीताल और चंपावत जिले के कुछ हिस्सों में भी सुबह में कोहरा छाए रहने की संभावना जताई गई है। शहर में बृहस्पतिवार को कोहरा छाए रहने से सूखी ठंड ने परेशान किया। वहीं, पर्वतीय इलाकों में बीते कुछ दिनों पहले हुई बर्फबारी के चलते सुबह-शाम के तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है।

पुण्यतिथि पर गांधी जी को किया नमन

रुद्रपुर (उद संवाददाता)। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर कांग्रेसियों ने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उन्हें नमन किया और उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का आह्वान किया। रुद्रपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम लंबाखेड़ा में रुद्रपुर कांग्रेस महानगर अध्यक्ष ममता रानी के नेतृत्व में तमाम कांग्रेसियों ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के चित्र पर माल्यार्पण कर उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। कांग्रेस महानगर अध्यक्ष ममता रानी ने कहा

कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी देश की आजादी के संवाहक बने। जिन्होंने शांति का संदेश देकर देश को एक सूत्र में बांधा और इस देश को आजाद कराया। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी देश की आजादी के नायक रहे हैं और आज भी कांग्रेस पार्टी उनके आदर्शों को आत्मसात कर देश के विकास में अपना योगदान दे रही है। उन्होंने महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें शत-शत नमन किया। इस दौरान पूर्व पालिकाध्यक्ष मीना शर्मा, अनिल शर्मा, नरेश सागर, मुनव्वर अली, अरविंद सक्सेना, अनीता ,नथिया देवी, मकसूद अली, बलबीर, जफर अली, शरीफ अहमद, इकबाल हुसैन, फुर्सत अली समेत तमाम लोग मौजूद थे।

राज्यपाल को सौंपा गया लोक सेवा आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन

देहरादून (उद संवाददाता)। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (से नि) से गुरुवार को लोक भवन में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष डॉ. रवि दत्त गोदियाल और आयोग के सदस्यों ने शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान आयोग की टीम ने राज्यपाल को अपना वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया और वर्तमान में संचालित विभिन्न गतिविधियों व भविष्य की योजनाओं की विस्तृत जानकारी साझा की। राज्यपाल ने आयोग की नवाचारी पहलों की सराहना करते हुए तकनीक के अधिकतम उपयोग और पारदर्शिता, निष्पक्षता व जवाबदेही के उच्चतम मानकों को बनाए रखने पर बल दिया।राज्यपाल ने आयोग को सुझाव दिया कि पिछले 25 वर्षों के अनुभवों, चुनौतियों और उपलब्धियों को संकलित कर एक पुस्तक प्रकाशित की जाए, ताकि भविष्य के लिए एक बेहतर कार्यप्रणाली का मार्ग प्रशस्त हो सके। उन्होंने अन्य राज्यों के लोक सेवा आयोगों में अपनाई जा रही ऐसी होनी चाहिए जिससे मेधावी युवाओं का भरोसा सिस्टम पर और अधिक मजबूत हो।भेंट के दौरान आयोग के अध्यक्ष ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025

श्रेष्ठ प्रक्रियाओं का अध्ययन कर उन्हें उत्तराखंड में भी लागू करने की बात कही। राज्यपाल ने जोर दिया कि चयन प्रक्रिया में विभिन्न परीक्षाओं के माध्यम से कुल 3,149 अभ्यर्थियों की चयन संस्तुति शासन को भेजी गई है। उन्होंने भविष्य की योजनाओं पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उत्तर पुस्तिकाओं के डिजिटल मूल्यांकन की प्रक्रिया पर तेजी से काम चल रहा है, जिससे मूल्यांकन प्रणाली पूरी तरह त्रुटिरहित और पारदर्शी बनेगी। साथ ही अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए एक विशेष मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किया जा रहा है, जिससे उन्हें परीक्षाओं से जुड़ी हर सूचना सीधे प्राप्त होगी। इसके अलावा अभ्यर्थी जल्द ही वेबसाइट पर लॉग-इन कर अपने प्राप्तांक देख सकेंगे, इसके लिए नई व्यवस्था तैयार की जा रही है।इस अवसर पर लोक सेवा आयोग के सदस्य अनिल कुमार राणा, नंदी राजू श्रीवास्तव, डॉ. रिचा गौर, सचिव अशोक कुमार पांडे, परीक्षा नियंत्रक जयवर्धन शर्मा एवं व्यवस्थाधिकारी सुनील भट्ट उपस्थित रहे।

कार्यालय नगर निगम रुद्रपुर ऊधम सिंह नगर

e-mail-nagarnigamrudrapur@gmail.com Visit-www.nagarnigamrudrapur.com

दूरभाष- 05944-242400

ई-निविदा सूचना

नगर निगम रूद्रपुर एवं विभिन्न शासकीय/अर्द्धशासकीय विभागों/निगमों में सिविल निर्माण कार्यों हेतु पंजीकृत ठेकेदार/फर्मों को सूचित किया जाता है कि नगर निगम रूद्रपुर द्वारा 15 वीं वित्त/राज्य वित्त की अनुदान एवं अन्य मद की धनराशि के अन्तर्गत निम्नांकित निर्माण कार्यों की ई-निविदा आमंत्रित की जाती है। ई-निविदा से सम्बन्धित समस्त जानकारी उत्तराखण्ड शासन की वेबसाईट www.uktender.gov.in एवं नगर निगम रूद्रपुर की वेबसाईट www.nagarnigamrudrapur.com पर दिनांक 30.01.2026 से अवलोकित की जा सकती है तथा उत्तराखण्ड शासन की वेबसाईट www.uktender.gov.in से डाउनलोड व भरी हुई निविदा अपलोड की जा सकती है। अधिक जानकारी नगर निगम निर्माण अनुभाग के कक्ष संख्या 23 से किसी भी कार्यालय कार्य दिवस में प्रातः 10:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक प्राप्त की जा सकती है।

क्र0 सं0	कार्य का नाम	आंगणन धनराशि (लाख में)
1.	नगर निगम रूद्रपुर क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न वार्डों में हॉटमिक्स कर सड़कों का निर्माण कार्य। (फेज-1)	494.68
2.	देवभूमि रजत जयंती के अन्तर्गत वार्ड नं0-3 ट्रांजिट कैम्प रूद्रपुर में सुभाष पार्क का सौन्दर्यीकरण कार्य।	159.24
3.	नगर निगम रूद्रपुर क्षेत्रान्तर्गत वार्ड नं0-28 में स्थित सब्जी मण्डी में पूर्ण रूप से अस्थाई टीन शैड की स्थापना एवं सी0 सी0 सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	48.19
4.	वार्ड नं0 38 स्थित राजकुमार खनिजो के होटल से रमेश कालड़ा के घर तक सड़क के दोनों तरफ नालों एवं विभिन्न पुलियों का निर्माण कार्य।	40.15

(शिप्रा जोशी पाण्डेय)
नगर आयुक्त
नगर निगम रुद्रपुर (ऊधमसिंह नगर)

(विकास शर्मा)
महापौर
नगर निगम रुद्रपुर (ऊधमसिंह नगर)

पत्रांक- 2824/सा.नि.अनु./ई-नि.सू./2025-26 दिनांक- 28.01.2026

कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी उधम सिंह नगर

Emaill-cmousnagar@gmail.com, Ph.-05944-2421114, Fax-05944-24739

जिला कुष्ठ निवारण समिति उधम सिंह नगर

(डा0 के0के0 अग्रवाल)
मुख्य चिकित्सा अधिकारी
उधम सिंह नगर

(श्री नितिन भदौरिया)
जिला अधिकारी
उधम सिंह नगर

पत्रांकः एन0एच0एम0/प्रचार/25-26/ दिनांक /01/2026

दन्या में बहुउद्देशीय विधिक जागरूकता शिविर आयोजित

अल्मोड़ा (उद संवाददाता)। उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के निर्देशन और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अल्मोड़ा के अध्यक्ष श्रीकांत पाण्डेय के मार्गदर्शन में रामलीला ग्राउंड दन्या में विशाल बहुउद्देशीय विधिक जागरूकता एवं साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव शचि शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित इस शिविर का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस दौरान सचिव शचि शर्मा ने उपस्थित जनसमूह और विद्यार्थियों को नालसा, सालसा और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की स्थापना व उनके कार्यों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने महिलाओं, बच्चों, ट्रांसजेंडर और वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों पर प्रकाश डालते हुए नालसा टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 15100, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 और निःशुल्क विधिक सहायता योजना के बारे में जागरूक किया।शिविर में जनहित से जुड़ी विभिन्न सेवाओं का लाभ मौके पर ही प्रदान किया गया। स्वास्थ्य विभाग द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण कर दवाइयां वितरित की गईं और दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनाए गए। वहीं हैडाखान चौरिटेबल ट्रस्ट चिलियानौला रानीखेत के सहयोग से नेत्र परीक्षण कर जरूरतमंदों को चश्मे बांटे गए। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने स्टॉल लगाकर अपनी जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी और पात्र लाभार्थियों को लाभान्वित किया। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेने वाले छात्र-छात्राओं को प्रमाण पत्र और अन्य लाभार्थियों को छड़ी व कान की मशीनें भी प्रदान की गईं।समारोह में उप जिलाधिकारी सौम्या गर्बियाल, उप शिक्षा अधिकारी दीक्षा बेलवाल, खंड विकास अधिकारी रोहित वर्मा, प्रभारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अरविंद पागती, थानाध्यक्ष दन्या दिनेश नाथ महंत और ब्लॉक प्रमुख लीला बिष्ट प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। शिविर में विभिन्न विद्यालयों के बच्चों ने सरस्वती वंदना, स्वागत गीत और कुमाऊंनी नृत्य की आकर्षक प्रस्तुतियां दीं। सचिव शचि शर्मा ने विभागीय स्टॉलों का निरीक्षण कर जनता को दी जा रही सहायता का जायजा लिया। द्वाराहाट, ताकुला और अल्मोड़ा के अधिकार मित्रों ने हेल्प डेस्क के माध्यम से लगभग 700 कानूनी पंफ्लेट बांटे। शिविर के माध्यम से कुल एक हजार से अधिक लोग लाभान्वित हुए।

ग्राम सुयालबाड़ी व नथुआखान में वितरित किए अखरोट के पौधे

हल्द्वानी (उद संवाददाता)। ग्राम सुयालबाड़ी में सरकार जन जन के द्वार अभियान कार्यक्रम के दौरान आशुतोष पन्त पूर्व जिला आयुर्वेद अधिकारी/पर्यावरणविद द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में शीतकालीन वृक्षारोपण अभियान के तहत नैनीताल जिले के सुयालबाड़ी में ग्रामीणों को अखरोट के पौधे भेंट किए। कार्यक्रम में आसपास के गांवों के तीन सौ से ज्यादा लोग आए थे। यहां विधायक सरिता आर्या और दर्ज राज्य मंत्री नवीन वर्मा के निर्देशन में आम जनता की विभिन्न

विभागों से संबंधित समस्याओं का निदान किया गया। जिला विकास अधिकारी गोपाल गिरी गोस्वामी सहित कई विभागों के अधिकारी/कर्मचारी मौजूद रहे। लोगों को कृषि, पशुपालन, सिंचाई, समाज कल्याण से संबंधित सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने के साथ चिकित्सा सेवा भी उपलब्ध कराई गई थी। कार्यक्रम समापन के बाद डा. आशुतोष पंत द्वारा उपस्थित ग्रामीणों को उपलब्ध कराए गए अखरोट के पौधे निःशुल्क भेंट किए गए। डा. पंत ने विधायक सरिता आर्या व दर्जा राज्य मंत्री नवीन वर्मा व समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों का सहयोग के लिए धन्यवाद व्यक्त किया। श्री वर्मा के निजी सचिव विष्णु, स्टाफ सागर, भाजपा मंडल अध्यक्ष नीरज बिष्ट का पौध वितरण व्यवस्था में सहयोग के लिए आभार जताया। उन्होंने बताया कि आज नाथूआखान/रामगढ़ में ग्रामीणों को उनकी भूमि में लगाने के लिए अखरोट के पौधे भेंट किए गए।

भाजपा शक्तिफार्म मंडल के विभिन्न मोर्चा अध्यक्षों की घोषणा

राजा हल्दार को युवा मोर्चा की कमान

शक्तिफार्म (उद संवाददाता)। भारतीय जनता पार्टी जिला ऊधम सिंह

नगर के जिला अध्यक्ष कमल कुमार जिंदल की सहमति और समस्त जिला मोर्चा अध्यक्षों से विचार-विमर्श के बाद शक्ति फार्म मंडल के विभिन्न मोर्चाओं के अध्यक्षों की घोषणा कर दी गई है। संगठन को मजबूती देने के उद्देश्य से की गई इन नियुक्तियों में युवा और अनुभवी कार्यकर्ताओं को तरजीह दी गई है।नई घोषणा के अनुसार, युवा मोर्चा के अध्यक्ष पद की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी राजा हल्दार को सौंपी गई है। महिला मोर्चा की कमान मीनाक्षी विश्वास को दी गई है, जबकि किसान मोर्चा के अध्यक्ष के रूप में शंकर गोलदार को नियुक्त किया गया है। इसी प्रकार अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) मोर्चा के अध्यक्ष पद पर सेवा सिंह, अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष पद पर मुकेश कुमार और अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष के रूप में मंजीत सिंह को दायित्व सौंपा गया है।इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष गोविंद तालुकदार ने सभी नव नियुक्त पदाधिकारियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि पार्टी नेतृत्व ने जिन कार्यकर्ताओं पर विश्वास जताया है, वे सभी संगठन की रीति-नीति को जन-जन तक पहुँचाने का कार्य करेंगे। उन्होंने भरोसा जताया कि सभी नवनियुक्त अध्यक्ष बूथ स्तर पर संगठन को और अधिक सशक्त बनाएंगे और पार्टी की विचारधारा को मजबूती देने के लिए पूरी निष्ठा से कार्य करेंगे। गोविंद तालुकदार ने कहा कि भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता संगठन की रीढ़ है और ये सभी पदाधिकारी जनता के बीच सक्रिय रहकर आगामी समय में पार्टी को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे।

मंत्रियों पर सरकारी खजाना लुटाना दुर्भाग्यपूर्ण : साहू

हल्द्वानी (उद संवाददाता)। उत्तराखंड के मंत्रियों की यात्रा भत्ता में सीधे महीने में तीस हजार की बढ़ोत्तरी पर युवा कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष हेमन्त साहू ने आक्रोश जाहिर किया है। जारी बयान में उन्होंने कहा राज्य की धामी सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हो गई है। सरकार को प्रदेश के दिव्यांग, बुजुर्ग जनों, विधवा महिलाओं की पेंशन बढ़ाने के बजाय अपने नेताओं और मंत्रियों पर जिस तरीके से सरकारी खजाना लुटाया जा रहा है वह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रदेश पहले ही कर्ज, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, पलायन की मार से जूझ रहा है। उसके बावजूद मंत्रियों के आवागमन की खर्च सीमा 60 हजार से बढाकर 90 हजार करना समझ से परे है। साहू ने कहा विधवा, तलाक शुदा महिलाओं, दिव्यांगों, बुजुर्ग जनों को महंगाई के दौर में महज पंद्रह सौ रुपए से गुजारा करना पड़ रहा है। वहीं मंत्रियों पर लाखों रूपये महीने लुटाए जा रहे हैं।

जन-जन के द्वार पहुंची सरकार, नागरिक हो रहे लाभान्वित

देहरादून (उद संवाददाता)। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार द्वारा जनकल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए प्रदेशभर में 'जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार' अभियान के तहत विशेष कैंपों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में गुरुवार को प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में कुल 20 कैंप लगाए गए, जिनमें 18,673 लोगों ने पहुंचकर विभिन्न सरकारी सेवाओं और योजनाओं का सीधा लाभ उठाया। प्रशासन की इस पहल से आम जनता को एक ही छत के नीचे विभागीय सुविधाएं मिल रही हैं, जिससे उन्हें दफ्तरों की भागदौड़ से मुक्ति मिली है।राज्य सरकार की इस मुहिम के तहत अब तक पूरे प्रदेश में कुल 504 कैंप आयोजित किए जा चुके

हैं। इन कैंपों के माध्यम से अब तक 4,08,541 से अधिक नागरिकों को विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा जा चुका है। आंकड़ों के अनुसार, सरकार का यह प्रयास विशेष रूप से ग्रामीण, दूरस्थ और वंचित वर्गों के लिए जीवन रक्षक और सहायक सिद्ध हो रहा है। इन शिविरों के माध्यम से शासन और जनता के बीच की दूरी कम हुई है और पात्र व्यक्तियों को समयबद्ध तरीके से लाभ मिलना सुनिश्चित हुआ है।मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस अभियान की सफलता पर कहा कि राज्य सरकार का मुख्य उद्देश्य शासन को सीधे जनता के द्वार तक पहुंचाना है ताकि अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को भी योजनाओं का लाभ मिल सके। उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि इन कैंपों की गुणवत्ता, पारदर्शिता और प्रभावशीलता में कोई कमी न आने दी जाए। प्रदेश में निरंतर आयोजित हो रहे ये शिविर सुशासन और सेवा के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शा रहे हैं, जिससे आम जनता के बीच प्रशासन के प्रति विश्वास और अधिक मजबूत हुआ है।

ओवरलोड और बिना टैक्स वाले वाहनों के खिलाफ चला अभियान

सितारगंज (उद संवाददाता)। परिवहन विभाग ने क्षेत्र में सड़क सुरक्षा को लेकर सघन चेकिंग अभियान चलाते हुए नियम तोड़ने वाले वाहन स्वामियों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। बृहस्पतिवार को चलाए गए इस अभियान के तहत विभाग ने दर्जनों ओवरलोड और ओवर हाइट वाहनों को पकड़कर उनके खिलाफ सीज और चालान की कार्रवाई की। इस अचानक हुई कार्रवाई से क्षेत्र के वाहन चालकों और ट्रांसपोर्टरों में हड़कंप मच गया।परिवहन विभाग के कर अधिकारी तारकेंद्र वार्ष्णेय ने टीम के साथ क्षेत्र के विभिन्न मार्गों पर औचक निरीक्षण किया। इस दौरान टीम ने ओवरलोडिंग और ओवर हाइट पाए गए ट्रकों व कैंटरों समेत चार बड़े वाहनों को मौके पर ही सीज कर दिया। इसके अलावा सड़क पर बिना टैक्स चुकाए (टैक्स पैड) दौड़ रहे वाहनों, बिना हेलमेट दुपहिया चालकों और नियमों का उल्लंघन करने वाले ई-रिक्शाओं के खिलाफ भी चालानी कार्रवाई की गई। विभाग की इस

सख्ती को देखकर कई वाहन चालक डर के मारे अपने वाहन सड़कों के किनारे खड़े कर वहां से हट गए, जिससे कुछ समय के लिए सड़कों पर सन्नाटा पसर गया।परिवहन अधिकारी ने बताया कि बढ़ते कोहरे को देखते हुए रोड सेफ्टी अभियान को और अधिक व्यापक बनाया जा रहा है। सुरक्षित यातायात के लिए साइन बोर्ड और क्रॉसिंग पर सुरक्षा इंतजामों का जायजा भी लिया जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सड़क सुरक्षा के मानकों से समझौता करने वालों के खिलाफ यह अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेगा।

पेज एक का शेष...

भूमि विवाद मामले ...स्तरीय विकास प्राधिकरण ने उक्त भूमि पर हो रहे निर्माण को अवैध बताते हुए ध्वस्तीकरण का नोटिस दिया था। शिकायतकर्ता का आरोप है कि जब वह मौके पर पहुंचे, तो विधायक के भाई और उनके साथियों ने उन्हें कागजात फेंककर जान से मारने की धमकी दी और दोबारा वहां न दिखने की चेतावनी दी। अरविंद पांडे पिछले लंबे समय से प्रदेश की राजनीति में सुर्खियों में बने हुए हैं। पूर्ववर्ती सरकार में शिक्षा और खेल मंत्री रहे पांडे का धामी सरकार की दूसरी पारी में सफर काफी तल्ख रहा है और उन्होंने ऊधम सिंह नगर के कई मामलों पर शासन-प्रशासन के खिलाफ मुखर होकर आवाज उठाई है। राजनीतिक गलियारों में इस मामले को भाजपा के भीतर जारी आंतरिक खींचतान से भी जोड़कर देखा जा रहा है। हाल ही में जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उत्तराखंड दौरे पर थे, तब पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत सहित कई वरिष्ठ नेताओं ने अरविंद पांडे के साथ खड़े होकर एकजुटता का संदेश दिया था जिससे संकेत मिले थे कि यह विवाद अब दिल्ली दरबार तक पहुंच चुका है। विधायक पांडे ने साफ कर दिया है कि वह जांच से भागने वाले नहीं हैं और चाहते हैं कि नार्को टेस्ट के माध्यम से सच्चाई जनता के सामने आए।

महाकाल के दर्शन कर ...सुनील मिगलानी न केवल एक सफल व्यवसायी थे, बल्कि वे योग ग्रुप के सक्रिय सदस्य के रूप में लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए सामाजिक कार्यों में भी बढ़-चढ़कर हिस्सा लेते थे।उनके निधन पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए क्षेत्रीय विधायक तिलक राज बेहड़, पूर्व विधायक राजेश शुक्ला, भाजपा नेता संजीव सिंह और देवभूमि व्यापार मंडल के नगर अध्यक्ष विजय अरोड़ा ने इसे व्यक्तिगत क्षति बताया है। शोक संवेदना व्यक्त करने वालों में महामंत्री नितिन फुटेला, राजेश मिगलानी, प्रदीप नारंग, अशोक चड्ढा, सुभाष चड्ढा, अनु मिगलानी, कैलाश खन्ना, संजीव खन्ना, महेंद्र फुटेला, मदन मदान, राजेश सिंगला, ओम तनेजा, राजकुमार तनेजा, मुकेश सिंधी, देवेंद्र सिंह मंड, नीरज नागपाल, दिनेश भाटिया, गुलशन सिंधी, निवर्तमान पालिका अध्यक्ष दर्शन कोली, भाजपा नगर व्यापार मंडल अध्यक्ष राजेंद्र सिंह उर्फ गोल्डी, जगरूप सिंह गोल्डी और कांग्रेस नगर अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी उर्फ बबलू चौधरी सहित सैकड़ों गणमान्य लोग शामिल हैं। सभी ने दिवंगत आत्मा की शांति और शोक संतप्त परिवार को यह असीम दुख सहने की शक्ति प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना की है। सुनील मिगलानी का अंतिम संस्कार उनके पार्थिव शरीर के किच्छा पहुंचने पर निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार किया जाएगा।

खड़े डंपर में ...सुनकर तुरंत मौके पर पहुंचे। कार की स्थिति देखकर लोगों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी और रेस्क्यू शुरू किया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद कार से घायलों को बाहर निकाला। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें हायर सेंटर भेज दिया गया है। पुलिस ने दोनों वाहनों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है।

उत्तराखंड ने बढ़ाए... आम जनता को भी प्लास्टिक के सही निस्तारण के लिए प्रेरणा मिलेगी। नगर आयुक्त के अनुसार देहरादून नगर निगम ट्रायल बेस पर यह मशीन शहर के अन्य 50 स्थान पर भी लगाने जा रहा है। जिसमें प्रमुख पर्यटक स्थल, रेलवे, बस स्टेशन, शैक्षणिक संस्थान, पार्क, सरकारी भवन और शहर के मुख्य चौराहे शामिल हैं। नगर आयुक्त ने आगे बताया की प्लास्टिक वेस्ट से इकोनॉमी मॉडल के तर्ज पर फर्नीचर बनाने के अलावा रोड निर्माण समेत अन्य कार्यों में इस्तेमाल किए जाने की योजना है ताकि, सिंगल यूज प्लास्टिक को डिस्पोज किया सके साथ ही उसका जो वेस्ट है, उसे भी इस्तेमाल में लाया जा सके।

फीस वृद्धि को ...पिटाई करने का भी आरोप लगाया। मामले की जानकारी मिलने पर कई छात्र नेता विद्यालय आ पहुंचे व उन्होंने विद्यालय प्रबन्धन से बात की। लेकिन कोई समाधान नही निकला। जिसके बाद रोषित छात्रों ने विद्यालय गेट पर नारेबाजी कर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। मामले की सूचना मिलने पर आदर्श कॉलोनी चौकी प्रभारी मौके पर पहुंचे और उन्होंने रोषित छात्रों व छात्रनेताओं से बातचीत की। जिसके बाद एक शिष्ट मण्डल ने विद्यालय प्रबन्धन से वार्ता की जिसमें प्रति विषय एक सौ रूपये फीस लिए जाने पर सहमती बनी। साथ ही सभी छात्रों को अपना गृह कार्य पूरा करने के निर्देश दिये गये। जिसके पश्चात छात्रों ने अपना धरना प्रदर्शन समाप्त किया।

सूचना नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है की मैंने अपना नाम राजिव ग्रोवर (RAJIV GROVER) से बदलकर राजीव ग्रोवर (RAJEEV GROVER) रख लिया है। भविष्य में मुझे राजीव ग्रोवर (RAJEEV GROVER) के नाम से जाना व पहचाना जाएगा।

राजीव ग्रोवर पुत्र इन्दर कुमार ग्रोवर, निवासी- ए-25, आदर्श कॉलोनी, रुद्रपुर, उधम सिंह नगर, उत्तराखंड

संस्थापक-स्व० हरनामदास सुखीजा एवं स्व०तिलकराज सुखीजा

स्वामित्वाधिकारी,प्रकाशक एवं मुद्रक परमपाल सुखीजा द्वारा उत्तरांचल दर्पण पब्लिकेशन्स, श्याम टाकीज रोड,रुद्रपुर,ऊधमसिंहनगर (उत्तराखण्ड) से मुद्रित एवं प्रकाशित

सम्पादक- परमपाल सुखीजा

आरएनआई नं.: UTTHIN/2002/8732 समस्त विवाद रुद्रपुर न्यायालय के अधीन होंगे।

E-mail-darpan.rdr@gmail.com,www.uttaranchaldarpan.in

फोन-245886(O)245701(Fax),9897427585,9897427586(Mob.)

वरिष्ठ नेता कस्तूरी लाल तागरा को मिला लोकतंत्र सेनानी सम्मान

महापौर विकास शर्मा के प्रयास प्रयास लाये रंग, शासन ने की सम्मान और पेंशन देने की संस्तुति

रुद्रपुर। रुद्रपुर के राजनीतिक एवं सामाजिक इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय जुड़ गया, जहाँ दशकों के लंबे इंतजार और प्रशासनिक जद्दोजहद के बाद वरिष्ठ भाजपा नेता कस्तूरी लाल तागरा को आखिरकार वह सम्मान प्राप्त हो गया है, जिसके वह वास्तविक हकदार थे। महापौर विकास शर्मा के भगीरथ प्रयासों के फलस्वरूप शासन ने कस्तूरी लाल तागरा को 'लोकतंत्र सेनानी' घोषित करते हुए उन्हें सम्मान और पेंशन देने का आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है। सम्मान मिलने पर महापौर ने कहा कि यह उपलब्धि न केवल एक व्यक्ति की जीत है, बल्कि आपातकाल के उस काले दौर में लोकतंत्र की मशाल जलाने वाले हर सेनानी के त्याग का सम्मान है। विदित हो कि रुद्रपुर के आवास विकास निवासी कस्तूरी लाल तागरा ने वर्ष 1975 में देश पर थोपे गए आपातकाल के दौरान तानाशाही के विरुद्ध बिगुल फूंका था। उस दौरान उन्हें साढ़े 14 माह का समय जेल की कालकोठरी में बिताना पड़ा, लेकिन दुर्भाग्यवश स्वतंत्रता के इस रक्षक को लंबे समय तक न तो लोकतंत्र सेनानी का दर्जा मिल सका और न ही सरकार की ओर से मिलने वाली पेंशन का लाभ। श्री तागरा ने इस अधिकार को प्राप्त करने के लिए शासन से लेकर प्रशासन तक अनगिनत बार पत्राचार किया, परंतु विभागीय औपचारिकता के बीच उनका न्याय दबा रहा। मामले में निर्णायक मोड़ तब आया जब विकास शर्मा ने महापौर बनने के बाद इस मामले को अपने हाथ में लिया। महापौर ने इसे केवल एक प्रशासनिक कार्य न मानकर अपने वरिष्ठ मार्गदर्शक के आत्मसम्मान की लड़ाई माना। उन्होंने श्री तागरा की फाइल को व्यक्तिगत रुचि लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दरबार तक पहुँचाया और वहाँ प्राथमिकता के आधार पर पैरवी की। मुख्यमंत्री धामी ने मामले की गंभीरता और श्री तागरा के संघर्ष को देखते हुए तुरंत सचिव शैलेश बगौली को प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए। सचिव बगौली ने जिलाधिकारी से विस्तृत रिपोर्ट तलब की और अंततः

उत्तराखंड लोकतंत्र सेनानी सम्मान अधिनियम 2025 तथा विभिन्न पूर्ववर्ती शासनादेशों के आलोक में पेंशन की संस्तुति प्रदान कर दी गयी। शासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार कस्तूरी लाल तागरा को 14 जून 2017 से 13 अक्टूबर 2022 तक की अवधि के लिए 16 हजार रुपये प्रतिमाह के हिसाब से पेंशन भुगतान दिया जाएगा। वहीं, इसके उपरांत से वर्तमान तिथि तक बढ़ी हुई दर यानी 20 हजार रुपये प्रतिमाह की दर से पेंशन स्वीकृत की गई है। महापौर विकास शर्मा ने अपने कार्यालय में इस आदेश की जानकारी साझा करते हुए कहा कि आपातकाल के दौरान तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने जनसंघ और सामाजिक कार्यकर्ताओं का जो दमन किया था, भाजपा सरकार ने उन सेनानियों को सम्मान देकर उस ऐतिहासिक भूल को सुधारने का काम किया है। ऐसे ही लोकतंत्र सेनानियों में से एक कस्तूरी लाल तागरा भी थे जो इमरजेंसी के दौरान साढ़े 14 माह तक जेल में रहे। उन्होंने कहा कि सवाल सिर्फ पेंशन की राशि का नहीं था, बल्कि उस गरिमा और पहचान का था जिससे श्री तागरा को वंचित रखा गया था। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की संवेदनशीलता के कारण रुद्रपुर के एक सच्चे जनसेवक को उसका अधिकार मिला है, जो पूरे शहर के लिए हर्ष का विषय है। महापौर ने इसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और सचिव शैलेश बगौली का आभार जताया और सम्मान मिलने पर कस्तूरी लाल तागरा को बधाई दी। उन्होंने कहा कि आज खुशी मिल रही है कि हमारी सरकार ने ऐसे व्यक्ति को सम्मान दिया है जिसने जनसंघ के दौर से पार्टी की निस्वार्थ भावन से सेवा की। इस अवसर पर स्वयं कस्तूरी लाल तागरा ने भी अपनी स्मृतियों को साझा करते हुए उन कठिन दिनों को याद किया। उन्होंने बताया कि 1975 में जब इंदिरा गांधी के आदेश पर दमनकारी नीति अपनाई गई, तब वह लखनऊ विश्वविद्यालय में छात्र राजनीति के माध्यम से लोकतंत्र बचाने की मुहिम में जुटे थे। विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के रूप में उनके विरुद्ध वारंट जारी हुआ और उन्होंने पुलिसिया दमन के विरुद्ध सत्याग्रह किया। परिणाम स्वरूप उन्हें लखनऊ कारागार में साढ़े 14 माह तक बंदी बनाकर रखा गया और अमानवीय यातनाएं दी गईं। श्री तागरा ने महापौर विकास शर्मा, मुख्यमंत्री धामी और सचिव शैलेश बगौली का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि आज यह महसूस हो रहा है कि उनके द्वारा झेली गई यातनाएं और निस्वार्थ सेवा सार्थक हुई है।

उत्तराखंड की 'हिमालयन ट्राउट' का दुबई में जलवा

हर महीने 20 टन मछली की मांग

शक्तिफार्म/सितारगंज (उद संवाददाता)। उत्तराखंड की हिमालयन ट्राउट मछली अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी धाक जमाने के लिए तैयार है। संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के दुबई में आयोजित वैश्विक खाद्य प्रदर्शनी 'गल्फ फूडख्र2026' में उत्तराखंड के उत्पादों को जबरदस्त सराहना मिली है। विशेष रूप से हिमालयन ट्राउट ने विदेशी खरीदारों को इस कदर प्रभावित किया है कि वहां से हर महीने लगभग 20 टन मछली की मांग सामने आई है। यूएई दौरे पर मौजूद प्रदेश के पशुपालन, मत्स्य एवं गन्ना विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा ने दूरभाष पर बताया कि अंतरराष्ट्रीय मानकों को पूरा करने के लिए सितारगंज में एक अत्याधुनिक एक्वा पार्क स्थापित किया जा रहा है। यहां ट्राउट मछली की प्रोसेसिंग और अंतरराष्ट्रीय स्तर की पैकेजिंग यूनिट लगाई जाएगी। इस यूनिट में मछली के 250 से 300 ग्राम के रेडी-टू-कुक पीस तैयार कर ग्लोबल मार्केट के लिए पैक किए जाएंगे। कैबिनेट मंत्री ने जानकारी दी कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में 3 किलोग्राम वजन की मछली की मांग अधिक है, जबकि वर्तमान में राज्य में औसत वजन 2 किलोग्राम तक है। इसे बढ़ाने के लिए सरकार मछली पालकों को अनुदान पर पौष्टिक आहार उपलब्ध कराएगी। उन्होंने लक्ष्य निर्धारित किया है कि अगले 6 माह में निर्यात की सभी कानूनी औपचारिकताएं पूरी कर ली जाएंगी और 7 माह के भीतर 20 टन ट्राउट मछली का पहला कंटेनर यूएई भेजा जाएगा। मंत्री बहुगुणा ने कहा कि इस पहल से राज्य के मछली पालकों की आय में भारी वृद्धि होगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। गल्फ फूड-2026 में सचिव डॉ. बीवीआरसी पुरुषोत्तम और गन्ना आयुक्त त्रिलोक सिंह मर्तोलिया सहित कई उच्चाधिकारी भी निवेशकों के साथ चर्चा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के 'वोकल फॉर लोकल' मंत्र को साकार करते हुए राज्य सरकार का लक्ष्य देवभूमि की ट्राउट को एक 'ग्लोबल ब्रांड' बनाना है। आने वाले समय में उत्तराखंड की यह मछली दुबई के रास्ते दुनिया भर की थाली तक पहुंचेगी।

शक्तिफार्म की शहरी बस्तियों के नियमितीकरण की मांग तेज

शक्तिफार्म (उद संवाददाता)। नगर पंचायत शक्तिफार्म क्षेत्र की शहरी बस्तियों में लंबे समय से रह रहे नागरिकों को भूमि स्वामित्व दिलाने की मांग एक बार फिर जोर पकड़ने लगी है। इसी क्रम में शास्त्री नगर निवासी वरिष्ठ भाजपा नेता एवं पूर्व सभासद रमेश राय ने नगर पंचायत की अधिशासी अधिकारी प्रियंका रैकवाल को एक लिखित आवेदन सौंपकर बस्तियों के नियमितीकरण की मांग की है। उन्होंने आग्रह किया है कि शहरी क्षेत्र में बने कच्चे और पक्के आवासों की रजिस्ट्री कर नागरिकों को मालिकाना हक प्रदान किया जाए।सौंपे गए आवेदन में बताया गया है कि नगर पंचायत शक्तिफार्म के अंतर्गत आने वाले विभिन्न वार्डों में अनेक परिवारों ने वर्षों पूर्व जमीन अथवा प्लॉट खरीदकर अपने आवास बनाए हैं, लेकिन आज तक उन्हें कानूनी रूप से भूमि का स्वामित्व प्राप्त नहीं हो पाया है। इस कारण आम नागरिकों

को कई प्रशासनिक और सामाजिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। प्रार्थना पत्र में उल्लेख किया गया है कि नगर पंचायत के वार्ड संख्या 1 से 7 तक बड़ी संख्या में ऐसे परिवार निवासरत हैं, जिन्होंने विधिवत भूमि खरीदी है। यदि शासन से अनुमोदन प्राप्त कर इन बस्तियों का नियमितीकरण किया जाता है, तो इससे हजारों परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी और नगर के नियोजित विकास को भी गति मिलेगी।रमेश राय ने प्रशासन से जनहित में शीघ्र कार्रवाई करने की मांग करते हुए कहा कि यह कदम सामाजिक न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण होने के साथ ही नगर पंचायत की आय बढ़ाने में भी सहायक होगा। अधिशासी अधिकारी प्रियंका रैकवाल ने इस संबंध में आश्वासन देते हुए बताया कि उक्त मामले में शासन को जल्द ही पत्र के माध्यम से सूचित कर आवश्यक दिशा-निर्देश मांगे जाएंगे। इस दौरान वार्ड 2 की सभासद सुशीला राय, वार्ड 1 की सभासद सुनीता सरकार, परेश मण्डल, प्रकाश मण्डल, मनोज ब्रह्म, कमलेश हालदार सहित अन्य स्थानीय नागरिक मौजूद रहे, जिन्होंने इस मांग का पुरजोर समर्थन किया है।

जल्द लागू होगी देवभूमि परिवार पहचान पत्र योजना

देहरादून। प्रदेश में नियोजन विभाग की ओर से जल्द ही देवभूमि परिवार पहचान पत्र योजना लागू की जाएगी। इसके लिए शासन स्तर पर एक एक्ट तैयार किया जा रहा है जो कि आगामी कैबिनेट में लाया जाएगा। इसके बाद मार्च में होने वाले बजट सत्र के दौरान सदन पटल पर रखा जाएगा। पिछले साल नवंबर में हुई कैबिनेट की बैठक में देवभूमि परिवार योजना को मंजूरी मिली थी। हरियाणा की तर्ज पर केंद्र व राज्य की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ लाभार्थियों तक पहुंचाने के लिए परिवार पहचान पत्र बनाने का निर्णय लिया गया था। नियोजन विभाग ने इस योजना को लागू करने के लिए अलग प्रकोष्ठ बनाया था। पोर्टल भी तैयार किया गया है। प्रमुख सचिव नियोजन आर मीनाक्षी सुंदरम ने बताया कि देवभूमि परिवार पहचान पत्र योजना को कानूनी रूप से लागू करने के लिए एक्ट बनाया जा रहा है। एक्ट का प्रस्ताव फरवरी में कैबिनेट में लाया जाएगा।इसके बाद मार्च में गैरसैंण में होने वाले बजट सत्र के दौरान सदन पटल पर रखा जाएगा। विधानसभा से पास होने के बाद एक्ट लागू हो जाएगा। संभावना जताई जा रही है कि मार्च में ही प्रदेश में यह योजना लागू हो जाएगी।